● वर्ष-4
● अंक-83
रायपुर, शुक्रवार
15 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» बिना तेल और घी के जलता है दीया...

नई औद्योगिक नीति रोजगार परक हैः मुख्यमंत्री साय

नई औद्योगिकी नीति 2024-30 जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज शाम नवा रायपुर के मेफेयर रिसार्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लांच किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपये प्रतिमाह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है।

हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है, आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का ''हेल्थ हब'' बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर के नजदीक हम लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व के ''न्यूनतम 20 एकड़ भूमि'' के स्थान पर अब हमने ''15 एकड़ भूमि'' पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

नक्सल पीड़ितों को विशेष अनुदान

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ संभवतः देश में पहला राज्य है, जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धन्धे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रूपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।

सुको ने महिला सरपंच को किया बहाल

पद से हटाने के आदेश को रद्द

नई दिल्ली। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने निर्माण कार्य में देरी के बहाने निर्वाचित महिला सरपंच को अनुचित रूप से परेशान करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मामले की सुनवाई की। आदेश में कहा यह एक निर्वाचित सरपंच को हटाने में अधिकारियों की ओर से उच्च मनमानी का मामला है, जो एक युवा महिला है जिसने छत्तीसगढ़ राज्य के एक दूरदराज के इलाके में अपने गांव की सेवा करने के बारे में सोचा था। उसकी प्रतिबद्धताओं की प्रशंसा करने या उसके साथ सहयोग करने या मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय, अपीलकर्ता अपने गांव के विकास के लिए जो करना चाहता था, उसके साथ बिल्कुल अवांछित और अनुचित कारणों से अन्याय किया गया है ... कार्यों के निर्माण में मौसम की अनियमितताओं के अलावा इंजीनियरों, ठेकेदारों और सामग्री की समय पर आपूर्ति शामिल होती है ... निर्माण कार्यों में देरी के लिए एक सरपंच कैसे जिम्मेदार हो सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि कार्य के आवंटन या निर्वाचित निकाय को सौंपे गए विशिष्ट

कर्तव्य के प्रदर्शन में देरी हुई थी ... हम संतुष्ट हैं कि कार्यवाही शुरू करना एक कमजोर बहाना था और अपीलकर्ता को सरपंच के कार्यालय से एक या दूसरे झूठे बहाने से हटा दिया गया है। आक्षेपित आदेशों को तदनुसार रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता अपना कार्यकाल पूरा होने तक ग्राम पंचायत के सरपंच का पद धारण करती रहेगी। चूंकि अपीलकर्ता को परेशान किया गया है और परिहार्य मुकदमेबाजी के अधीन किया गया है, हम उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना देते हैं , जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 4 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा, न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को अपीलकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर 1 लाख रुपये की लागत जारी करने का निर्देश दिया, और उसके बाद, उसके उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने के लिए जांच करें। अदालत ने कहा, राज्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। संक्षेप में कहें तो अपीलकर्ता, एक 27 वर्षीय महिला, ने 2020 में आयोजित सेजबहार ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ा था। वह अच्छे अंतर से चुनी गई थीं। ग्राम पंचायत को कुछ विकास कार्य आवंटित किए गए, जिनमें सड़कों के 10 निर्माण कार्य आदि शामिल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 16.12.2022 को 3 महीने के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए जारी किया गया एक पत्र मार्च, 2023 में ग्राम पंचायत को दिया गया था।

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया गया था। याचिका झारखंड विधानसभा और अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ सुनवाई के लिए राजी हुई। याचिका में हाईकोर्ट के 23 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने बिना किसी आपराधिक मामले के सीबआई को जांच का आदेश दिया। यह एक नागरिक मामले से जुड़ा हुआ केस है। राज्य की पुलिस, जांच एजेंसी मामले की जांच करने में सक्षम है और जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश सही नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है और न ही कोई आपराधिक मामला है, जिसके आधार पर जांच शुरू की जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि मामले में पैसे के लेन-देन का कोई सबूत नहीं है और न ही कोई धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है।

गोवा के मुख्य सचिव को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोवा के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई, जब उन्होंने राज्य सरकार के उस फैसले का बचाव किया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जारी नियमों में अवैध तरीके से बदला गया था। यह बदलाव हाईकोर्ट की गोवा पीठ के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से जुड़ा था। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उनसे अगली सुनवाई में निजी रूप से डिजिटल तरीके से पेश होने को कहा और उनके आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव का व्यवहार गलत है और यह बहुत गंभीर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गोवा सरकार द्वारा किए गए बदलाव को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा, क्या उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? यह एक बेशर्मी भरा कृत्य है।

जनजातीय गौरव दिवस महोत्सव का किया भव्य शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती के अवसर पर आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दो दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का देवगुड़ी में पूजा-अर्चना और दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत दो दिनों तक विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी के साथ-साथ देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दलों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा सहित शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुण्डाधुर को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करके जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस की भव्य शुरूआत 13 नवम्बर से जशपुर से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समुदाय की जितनी चिंता की है, उतनी किसी ने नहीं की है।

प्रदेशव्यापी धान खरीदी महापर्व का किया शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रदेशव्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ बालोद जिले के भांठागांव (बी) धान खरीदी केन्द्र से किया। इसी के साथ आज 14 नवम्बर राज्य में किसानों से धान खरीदी की शुरूआत हो गई है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। मुख्यमंत्री साय ने भांठागांव (बी) उपार्जन केन्द्र पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉनिक तौल एवं अन्य यंत्रों का पूजन और वहां उपस्थित किसानों को माला पहना कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसान भाईयों को धान खरीदी महापर्व के शुभारंभ की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ग्राम भांठागांव के किसान भागबली ने कुल 148 क्विंटल और हरिराम ने 65 क्विंटल 20 किलो धान की बिक्री की। मुख्यमंत्री के समक्ष अपने धान की बिक्री का अवसर प्राप्त होने से किसान भागबली और हरिराम बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उक्त उपार्जन केन्द्र में 14 नवम्बर को धान खरीदी हेतु कुल 06 किसानों का टोकन काटा गया है।

एक मंच पर दिखी विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों की अनूठी झलक

रायपुर। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दो दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए लोक नर्तक दलों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, नागालैण्ड, उत्तरांचल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दमन दीव, गुजरात और राजस्थान के जनजातीय समूह ने पारंपरिक लोकनृत्यों की प्रस्तुति दी।

प्रमुख समाचार

कांग्रेस ने नहीं कही 370 को बहाल करने की बातः खरगे

पुणे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का विरोध किया कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहती है। खरगे ने कहा कि अमित शाह झूठ फैला रहे हैं, कांग्रेस में किसी ने ऐसा नहीं कहा। खरगे ने कहा कि भाजपा समाज को बांटने के लिए अनुच्छेद 370 के मुद्दे को समाज को विभाजन के वास्ते चर्चा में बनाए रखना चाहती है। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा, अमित शाह चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे खुद कह रहे हैं कि काग्रेस अनुच्छेद 370 को फिर से लाना चाहती है। मुझे बताइए, किसने और कब ऐसा कहा? आप यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अगर यह (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रस्ताव) पहले ही संसद में पारित हो चुका था, तो अब यह मुद्दा क्यों उठाते हैं? इसका मतलब है कि आप इसे सिर्फ समाज में विभाजन पैदा करने के लिए उठाते हैं। अगर आपको यह कहा है, तो कश्मीर जाकर कहिए। कश्मीर में चुनाव खत्म हो चुके हैं। अनुच्छेद 370 कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था.

आप के महेश खींची बने एमसीडी के नए मेयर

नई दिल्ली। दिल्ली में आज हुए मेयर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एमसीडी में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार महेश खींची ने दिलचस्प मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार किशन लाल को तीन वोटो से हराया है। दरअसल, गुरुवार को दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर पद के चुनाव हुए। मेयर पद के लिए कुल 265 वोट पड़े जिनमें से दो वोटो को अमान्य कर दिया गया। आप उम्मीदवार महेश खींची को जहां 133 वोट मिले वहीं भाजपा उम्मीदवार किशनलाल को 130 वोट से संतोष करना पड़ा। ऐसे में दिल्ली में 7 महीने की देरी के बाद नए मेयर मिल गया है। महेश खींची शैली ओबेरॉय की जगह लेंगे। अब तक शैली ओबेरॉय एक्सटेंशन पर थीं। दिल्ली में हर साल मेयर का चुनाव अप्रैल में होता है। लेकिन इस साल यह चुनाव 7 महीने की देरी से हुई। इसका कारण यह है कि पीठासीन अधिकारी तय करने वाली फाइल यह कहकर लौटा दी गई थी कि इस पर सीएम का रिकमेंडेशन नहीं है। उस वक्त दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे।

यूपीपीसीसी के झुकने के बाद भी छात्र नहीं हटने को तैयार

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के झुकने के बाद भी प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है।

छात्र आयोग के दो नंबर गेट के सामने डंटे हुए हैं और हटने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की घोषणा की जाए, तभी उनका आंदोलन पूरी तरह से खत्म होगा। छात्रों की मांग यह है कि जिस तरह से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की घोषणा की गई है, उसी तरह आरओ-एआरओ परीक्षा भी वन डे वन शिफ्ट में कराने का लिखित आश्वासन दिया जाए, तभी वह धरना खत्म करेंगे। छात्रों का कहना है कि आरओ-एआरओ परीक्षा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का आश्वासन देकर आयोग प्रतियोगी छात्रों को बरगला नहीं सकता है। दोनों परीक्षाओं को एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। आयोग ने एक ही परीक्षा की मांग मानी है, जबकि आरओ एआरओ परीक्षा को एक दिन में कराने के लिए कोई फैसला नहीं किया है।

ताकतवर उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी इकलौते भारतीय

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 100 ताकतवर कारोबारियों में शामिल हैं। अंबानी %फॉर्च्यून मैगजीन% के पावरफुल बिजनेसमैन 2024 की सूची में शामिल होने वाले अकेले भारतीय हैं। इसमें भारतीय मूल के अन्य छह लोग भी शामिल हैं, जो विदेश में बसे हैं। ये लोग बड़े व्यवसायों के संस्थापक, मुख्य कार्यकारी और नवप्रवर्तक हैं। फॉर्च्यून ने हाल ही में इस सूची को जारी किया है। इसमें अंबानी को 12वें स्थान पर रखा गया है। फॉर्बस के मुताबिक, अंबानी एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 7.6 लाख करोड़ रुपये (98 अरब डॉलर) है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार पूंजी (मार्केट कैप) 13 नवंबर 2024 तक 16.96 लाख करोड़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है। अंबानी परिवार अगली पीढ़ी को अपने व्यापार साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं। छोटे बेटे अनंत अंबानी उर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

खालिस्तानी आतंकी प्रत्यर्पण तेज करेंगे प्रयास

नई दिल्ली। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी अर्श सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला की गिरफ्तारी के बाद भारत अब उसके प्रत्यर्पण की कवायद तेज करने में जुटा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने जुलाई 2023 में गिरफ्तारी के आग्रह के साथ कनाडा सरकार को अर्श डल्ला के बारे में तमाम जानकारियां मुहैया कराई थी। उम्मीद है कि अब भारत के अनुरोध पर उसे प्रत्यर्पित या निर्वासित किया जाएगा। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने 10 नवंबर को मीडिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख अर्श डल्ला की कनाडा में गिरफ्तारी की खबरें देखीं। हमें पता चला है कि मामले को ओंटारियो कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गिरफ्तारी के मद्देनजर हमारी एजेंसियां प्रत्यर्पण अनुरोध पर कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, कनाडाई प्रिंट और विजुअल मीडिया ने गिरफ्तारी के बारे में व्यापक रूप से रिपोर्ट की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत में अर्श डल्ला के आपराधिक रिकॉर्ड और कनाडा में इसी तरह की अवैध गतिविधियों में उसकी संलिप्तता को देखते हुए उसे भारत को सौंप दिया जाएगा। रणधीर जायसवाल ने कहा, डल्ला हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण समेत 50 से अधिक मामलों में घोषित अपराधी है।

लाल आतंकी साया मिटाकर ही जनजातीय गौरव लौटा सकेंगे

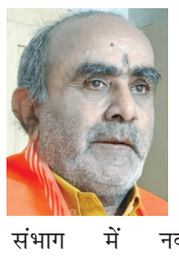

अनिल पुरोहित

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों (कम्युनिस्ट आतंकवादियों) द्वारा इसी सोमवार की रात बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में ग्राम पोटेनार में अपनी कथित जनअदालत लगाकर पुलिस मुखबिरी के आरोप में ग्राम माटवाड़ा के ग्रामीण माड़वी दुलारू की हत्या करने के बाद 15 नवम्बर को मनाए जाने वाले जनजाति गौरव दिवस के परिप्रेक्ष्य में जनजातीय समाज पर माओवादियों के प्रभाव पर विमर्श की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। पिछले अक्टूबर माह में भी नक्सली आतंकवादियों ने 8, 19 और 29 अक्टूबर को बस्तर के विभिन्न इलाकों में कन्हैया ताती, तिरुपति भंडारी और दिनेश पुजारी की हत्या करके दहशत फैलाने का काम किया था। और ऐसी ही कहानियाँ पिछले दो दशकों से लगातार हमें देश के जनजातिङ्कबहुल क्षेत्रों से लगातार सुनने में आ रही हैं। विश्व की एक प्रतिष्ठित संस्था साउथ एशिया टेररिस्ट पोर्टल की वेबसाइट पर प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार 2019 से लेकर अब तक निरपराध ग्रामीणों को गोली मारने की ऐसी 49 घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनमें कुल 69 लोगों की हत्या की गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 31 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1999 से 2019 तक 20वर्षों में देशभर में कुल 8,126 निर्दोष नागरिकों की हत्या इन माओवादियों ने की है। इसके अलावा कभी बारुदी सुरंग, तो कभी अन्धाधुन्ध फायरिंग, आदि से हताहत होकर जीवनभर के लिए पंगु हो जाने वाले लोगों की गणना तो अभी बाकी है। ऐसे ही, पिछले ढाई दशकों में अनेक विद्यालय, अस्पताल, पुल- पुलिया आदि इन माओवादियों ने ध्वस्त किये हैं। विकासपरक कार्यों में निरन्तर बाधा डालकर जनजातीय क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढाँचे जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्हें भारत सरकार के खिलाफ बन्दूकें उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। अपने सगे-सम्बन्धियों की हत्या के लिए विवश किया जा रहा है। शान्ति, उत्साह और मस्ती से भरा निश्चिन्त जीवन जीने वाले लोग दिन-रात अपनी और अपने परिवार की चिन्ता में लगे रहकर %दादालोगों% की गुलामी को विवश हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखण्ड, बंगाल, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में तो आए दिन माओवादी घटनाओं से जुड़ी ऐसी खबरें पढ़ने में आती रहती हैं। भले ही माओवादियों के शहरी तन्त्र के कारण इन घटनाओं का बाहर उल्लेख न के बराबर रहता है।

अब कुछ सवाल ये खड़े होते हैं कि वे चाहते क्या हैं? जब नक्सली खुद को सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोधी बताकर यह दावा करते हैं कि वे सरकारी दमन से जनजातीय समाज के जल-जंगल-जमीन की रक्षा कर रहे हैं, तो फिर वे सीधे-सादे निरपराध जनजातीय समाज के ग्रामीणों की हत्या क्यों कर रहे हैं? हम सब जिन्हें प्रायः नक्सली नाम से जानते हैं, वे खुद के संगठन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) क्यों कहते हैं? उनके पास आधुनिक हथियार कहाँ से आए? इन लोगों ने अत्याधुनिक खुफिया तंत्र कैसे विकसित कर लिए? चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ से भला इनका क्या लेना-देना? इन सवालों का जवाब हम ढूँढ़ें तो पता चलेगा कि दरअसल ये नक्सलवाद, नक्सली, भटके हुए लोग, जैसा कुछ है ही नहीं। यह एक विशुद्ध आतंकवाद है और नक्सली वास्तव में आतंकवादी हैं, जो पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने की सनक के साथ काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अबतक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं। माओ-प्रेरित ये आतंकवादी जनजातीय समाज की आड़ लेकर आतंक के रास्ते भारत की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए लाल-युद्ध चला रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस और सुरक्षाबलों के द्वारा विभिन्न आपरेशन्स में जब्त अनेक माओवादी दस्तावेज इस बात के प्रमाण हैं कि यह चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ त्से तुंग के सशस्त्र कम्युनिस्ट क्रान्ति के विचारों पर आधारित एक सुनियोजित युद्ध है और उसका एकमात्र लक्ष्य संविधान द्वारा स्थापित भारत की सत्ता को उखाड़कर उसकी जगह चीन की ही तरह कम्युनिस्ट तानाशाही को स्थापित करना है।

ऐसे में यह प्रश्न भी उठता है कि उन्होंने वन्य क्षेत्रों को ही क्यों चुना? तो इसका उत्तर है कि कम्युनिस्ट आतंकवादियों ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत जनजातीय क्षेत्रों को ही इसलिए चुना क्योंकि इन माओवादियों ने भारत के विरुद्ध जब सेना बनानी शुरू की तो वह भलीभाँति यह जानते थे कि भारतीय सेना के आगे तो वह टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने जंगलों को अपना अड्डा बनाया। घने वनों और उनमें रहने वाले जनजातीय समाज में उन्हें इस युद्ध के लिए अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने के साधन दिखाई पड़े, इसलिए ही उन्होंने इन दुर्गम स्थानों की शरण ली और फिर, वहाँ रह रहे जनजातीय समाज की-जीवन-पद्धति, उनकी संस्कृति, उनकी आस्था व आध्यात्मिक चेतना को अपनी दखलंदाजी से खत्म करने का कुचक्र चलाया। जाहिर है, ये जंगल माओवादियों के लिए बेहद सुरक्षित अड्डे बने भी और निश्छल, सहज-सरल जनजातीय समाज को उन्होंने आमना-सामना होने पर पुलिस व सेना के सामने अपने लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने और शहरी (अर्बन) नक्सलियों ने मिलकर दसियों झूठ गढ़कर न केवल जनजातीय समाज को दिग्भ्रमित किया, अपितु शेष समाज में भी जनजातीय समाज को लेकर तरह-तरह की भ्रांतियाँ फैलाकर ऐसा अलगाव पैदा किया जो इस्लाम और ब्रिटिशों के दौर में भी नहीं हो सका था। इन नक्सलियों ने झूठ का ऐसा मायाजाल रचा कि सबसे पहले तो जनजातीय समाज के (शेष पृष्ठ 3 पर)

भाजपा संगठन चुनाव में जगदलपुर के 98 बूथ के चुनाव प्रभारी, सहप्रभारी नियुक्त

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव के लिये प्रथम चरण में प्रत्येक बूथ में बूथ समिति के चुनाव होंगे। जिसके लिये प्रारंभिक तैयारियां तेज हो गयी है। आज भाजपा जिला कार्यालय में जगदलपुर नगर मण्डल के अन्तर्गत आने वाले 98 बूथ में होने वाले बूथ समिति निर्वाचन के लिये चुनाव प्रभारी, सहप्रभारी नियुक्त किया गया। जिसमें विशेष रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक किरण देव उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने संगठन चुनाव को सर्वोपरि बताते हुये बूथ समिति निर्वाचन कार्य को निर्धारित समय में तय मापदण्डों के साथ पूर्ण करने कहा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यशाला में कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान सफलता पूर्वक संपन्न हो रहा है। प्राथमिक सदस्यता के साथ सक्रिय सदस्यता का काम पूर्णता की ओर है। संगठन चुनाव की समस्त प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले बूथ समिति निर्वाचन होने है, जिसे गंभीरता से समय पर संपन्न करना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने नगर मण्डल के 15 शक्ति केन्द्र स्तर पर बनाये गये चुनाव प्रभारी व सहप्रभारी की जानकारी ली और सभी को बूथ समिति निर्वाचन कार्य बिन्दु बाबत अवगत कराया। कार्यशाला को सांसद महेश कश्यप, नगर मण्डल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मण्डल महामंत्री संग्राम सिंह राणा व आभार प्रदर्शन मण्डल उपाध्यक्ष राकेश तिवारी ने किया। कार्यशाला में प्रमुख रूप से विद्याशरण तिवारी, योगेन्द्र पाण्डेय, वेदप्रकाश पाण्डेय, रजनीश पानीग्राही, महापौर सफीरा साहू, नरसिंह राव, मनोहर तिवारी, आर्येन्द्र आर्य, दीप्ति पाण्डेय, सुधा मिश्रा, शशिनाथ पाठक, आलोक अवस्थी,राजपाल कसेर, दिगम्बर राव, निर्मल पाणिग्रही, मोतीलाल बघेल, यशवर्धन राव, धनसिंह नायक, रीना घोष, ममता पोटाई,प्रमीला कपूर, बसंती नायक, महेन्द्र पटेल, शंभू नाग, नरेंद्र पाणिग्रही, रंजीत पाण्डेय, योगेश ठाकुर, अभय दीक्षित, प्रकाश झा, संतोष बाजपेयी, श्रीपाल जैन, लाला महावर, रितेश सोनी, योगेश शुक्ल, खेमसिंह देवांगन, राजा यादव, अशोक नेताम, गोविन्द ईनाणी,आशुतोष पाल, सूर्य भूषण सिंह, रौशन झा,अमर झा, दिलीप झा,कौशिक शुक्ल,रामकुमार मण्डावी, वीरू शर्मा, मनोज ठाकुर,शैलेष श्रीवास्तव,कमल पटवा, श्रीष मिश्रा, हरीश पारेख, कृष्णा ठाकुर, विनोद पाण्डेय, सुरेश मिश्रा,दशरथ गुप्ता, भुवनेश्वर ध्रुव, गणेश काले आदि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कवर्धा में धान बेचने आए किसानों का सोसायटी कर्मचारियों ने फूल मालाओं से किया स्वागत

कवर्धा। कबीरधाम जिले में 90 समितियों के 108 सोसायटियों में धान खरीदी चल रही है। धान खरीदी के पहले दिन सोसायटी में आए किसानों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के बाद धान खरीदी का आगाज हुआ। जिले के सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमिट्रिक डिवाइस के जरिये धान की की खरीदी की जा रही है। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है।

कवर्धा में किसानों से धान खरीदी के लिए जिला प्रशासन ने 108 खरीदी केंद्र बनाए हैं। 90 समितियों के 108 खरीदी केंद्रों पर 7 हजार 280 नये पंजीकृत किसानों समेत 1 लाख 24 हजार 787 किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। किसानों ने 1 लाख 24 हजार 411 हेक्टेयर रकबे का समर्थन मूल्य में धान बेचने का पंजीयन कराया है। तय नियमों के तहत किसानों से धान की खरीदी हो सके इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। खरीदी में किसी तरह की कोई दिक्कत किसानों को नहीं आए इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अवैध धान परिवहन पर भी निगरानी रखी जा रही है। किसान ईश्वरी ने कहा धान बेचने के लिए हम पहले दिन केंद्र पर पहुंचे तो हमारा स्वागत सत्कार किया गया। हमें एक दिन पहले ही मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन टोकन मिल गया था। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। सोसायटी प्रबंधन हीरा साहू ने बताया शासन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक खरीदी की जा रही है। किसानों को एक दिन पहले ही टोकन दे दिया गया है।

धान खरीदी को लेकर किसानों के बीच जबरदस्त उत्साह है। सरकार ने चुनाव के वक्त ही किसानों से वादा किया था कि वो 3100 रुपए की दर से किसानों से धान की खरीदी करेगी। चुनाव जीतने के बाद साय सरकार ने अपना वादा पूरा किया।

धान के अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

कोंडागांव। कोंडागांव जिले में धान तिहार से पहले अवैध धान परिवहन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस दौरान जिले में अवैध धान परिवहन रोकने के लिए 21 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें 24 घंटे जांच कर रही हैं। इसके अलावा, पांच उड़नदस्ता टीमें भी निगरानी में जुटी हुई हैं, ताकि छोटे व्यापारियों एवं बिचौलियों पर नजर रखी जा सके। हाल ही में कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव के अंतर्गत अवैध रूप से धान क्रय-विक्रय करने पर पांच व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

बाफना पेट्रोल पंप का टैंक फटा, घर के कुएं से निकलने लगा पेट्रोल

प्रशासन ने पूरे इलाके को किया सील

दंतेवाड़ा। जिले के गीदम में वार्ड नंबर-12 के निवासी भोलू जैन के घर के कुएं से अचानक पेट्रोल निकलने लगा, जब शहर के लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो घर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लोग बाल्टियों से पेट्रोल निकालने लगे। खबर मिलते ही प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि करीब 100 मीटर दूरी पर स्थित बाफना पेट्रोल पंप का टैंक फट गया था, जिससे पेट्रोल जमीन के अंदर से रिसकर कुएं में पंहुच रहा था। प्रशासन ने बाफना पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया है। बताया जा रहा है कि गुरूवार को कंपनी के टेक्नीशियन आएंगे। साथ ही जमीन के अंदर दबी टंकी से पेट्रोल खाली कर टैंक को ठीक किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गीदम के पुराने बस स्टैंड में बाफना पेट्रोल पंप है, पंप मालिक ने कुछ दिन पहले गीदम पुलिस से शिकायत की थी कि, उसके पंप से पेट्रोल की चोरी हो रही है। हर दिन कई लीटर पेट्रोल कम हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गए, आस-पास में मुखबिर लगाकर नजर भी रखी गई। लेकिन चोरी की इस गुत्थी को पुलिस नही सुलझा पाई। वहीं, 13 नवंबर की शाम पेट्रोल पंप के ठीक पीछे स्थित वार्ड नंबर-12 के निवासी भोलू जैन के घर के कुएं से पेट्रोल निकलने लगा। घर वालों को पानी में पेट्रोल की गंध आने लगी। जिसके बाद उन्होंने कुएं में बाल्टी डालकर जब पानी निकाला तो उसमें से पेट्रोल निकला। यह खबर जब शहर में फैली तो लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है।

बुधवार देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की गई तो पता चला कि पेट्रोल पंप का टैंक फूटा हुआ है। जिसका पेट्रोल रिसकर घर के कुएं में पंहुच रहा था। जांच के बाद प्रशासन ने तत्काल पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया, साथ ही जिस घर के कुएं में पेट्रोल मिला, उसके आस-पास के इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। लोगों की आवा-जाही पर रोक लगा दी गई। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम, बिजली विभाग की टीम को भी उस पूरे इलाके में तैनात किया गया है। बाफना पेट्रोल पंप के मालिक ने पेट्रोल रिसने की जानकारी कंपनी को दी है। गीदम थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा ने कुएं से अचानक पेट्रोल निकलने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले की जानकारी मिलते ही जवान मौके पर पहुंचकर वहां से लोगों की भीड़ को हटाया गया। साथ ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके में रात भर जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी।

लुटेरी दुल्हन ने शादी का षड्यंत्र रचकर एक शख्स को लूटा

विवाह की तीसरी रात गहने और कैश लेकर फरार

महासमुन्द। देवउठनी पर्व के बाद अब शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में हम सबको चौकाने और सतर्क करने वाली तस्वीर सामने आई है। महासमुंद पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग का खुलासा किया है। जो पहले तो व्यक्ति को शादी के जाल में फंसाते हैं, उससे तीन लाख नगदी लेते है, फिर शादी करके तीसरी रात ही घर से सब गहने-जेवर और नगदी लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं। पुलिस ने गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ गैंग का रिकार्ड खंगालने में भी पुलिस जुटी हुई है।

देवउठनी पर्व के बाद अब देश प्रदेश में शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में लोग अब एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। लेकिन इसके दूसरी ओर महासमुंद पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब तक हम देश के अलग-अलग हिस्से में लुटेरी दुल्हन का गैंग के बारे में देखते और सुनते आ रहे थे। लागातार इससे जुड़े हुए मामले सामने आते रहती है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पहली बार सामने आया है। जहां पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। जो पहले व्यक्ति को शादी के जाल में फांसते है। गैंग का एक सदस्य उसकी शादी ओडिशा के एक लड़की से करवाने के नाम पर 3 लाख नगद लेता है। फिर बड़े ही शातिर तरीके से व्यक्ति की शादी मंदिर में कराई जाती है।

शादी के बाद तीसरी रात को लुटेरी दुल्हन घर के जेवरात और नगदी लेकर अपने दूसरे सदस्य के साथ नौ-दो ग्यारह हो जाती है। घटना के बाद पीड़ित पति ने महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के भंवरपुर चौकी में मामला दर्ज कराया था। पहला ऐसा मामला होने के कारण पुलिस ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जगह पर छापा मारा। आखिरकार अब पुलिस ने मामले का खुलासा किया है और लुटेरी दुल्हन के गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दरसल यह पूरा मामला महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के भंवरपुर चौकी का है। जहां 17 जून को पीड़ित पति हेमकुमार चौधरी ने अपनी पत्नी और उनके साथियों पर लूट का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि, तीन लाख नगद लेकर, 25 फरवरी को ओडिशा के सुहेला मंदिर में आरोपी गुप्ता सुनानी उर्फ राकेश, सुदामा पटेल और गोरखनाथ दास ने महिला ममता सराफ उर्फ ममता पटेल से उसकी शादी रचाई। शादी के बाद महिला दो रात घर में रूकी और तीसरी रात अपने एक सदस्य के साथ घर के जेवरात और नगदी लेकर रफूचक्कर हो गई। जब तक पीड़ित पति को ठगी का एहसास हुआ तब तक लुटेरी दुल्हन गैंग के सदस्य अपने मंसूबे को अंजाम दे चुके थे।

शादी करके लूटने का अब तक का यह महासमुंद जिले या कहें छत्तीसगढ़ में पहला मामला है। मामला सामने आने के बाद पुलिस की टीम हरकत में आई, इसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई जगह पर छापेमारी की गई। तब कहीं जाकर ओडिशा के खपराकोल बलांगीर से 2 आरोपी ममता और गुप्ता सुनानी पकड़े गए हैं। मामले में 2 आरोपियों ने प्राथमिक बेल ले लिया है। फिलहाल भंवरपुर पुलिस ने चारों आरोपियों पर धारा 419, 420, 406, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के पुराने रिकार्ड भी खंगालने में जुटी हुई है।

इस मामले के बाद पुलिस खुलासा में यह बात सामने आई कि, पीड़ित व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही थी। उम्र निकलता जा रहा था। लिहाजा उसे शादी की हड़बड़ी थी और यही कारण है कि पीड़ित व्यक्ति जालसाजी का शिकार हो गया। मामले के बाद अब महासमुंद पुलिस भी लोगों से शादी जैसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करने और पूछ परख के साथ पूरी बारीकी से जांच पड़ताल के बाद ही शादी करने की अपील कर रही है। ताकि किसी और के साथ इस तरह से कोई लुटेरी दुल्हन या फिर उसकी गैंग लूट की घटना को अंजाम न दे सके।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सड़क हादसे में बाल-बाल बचे एसडीएम और नायब तहसीलदार

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बीती रात ड्यूटी के बाद जिला मुख्यालय से देवभोग वापस लौटते समय स्ठरू तुलसी दास मरकाम सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। उनकी स्कॉर्पियो सीजी 30 डी 9997 नेशनल हाइवे 130 सी में अनियंत्रित होकर धवलपुर नाला के पास पलट गई। यह गाड़ी पलट कर जब टकराई तो वाहन के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में एसडीएम और स्कॉर्पियो चला रहे तहसीलदार विजय सिंह बाल-बाल बचे हैं। दोनों को मामूली चोंटे ही आई है। दरअसल, इस हादसे के वक्त गाड़ी की सेफ्टी के लिए दोनों एयरबैग्स खुले हुए थे, जिसकी वजह से दोनों की जान बच पाई है। दोनों को मामूली अंदरूनी चोंट आई है। घटना के बाद तत्काल एसडीएम तुलसी दास मरकाम व वाहन चला रहे नायब तहसीलदार विजय सिंह को आवाजाही कर रहे मददगार के द्वारा मैनपुर अस्पताल में ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। वहीं घटना के बाद वाहन को नाले से बाहर निकालकर धवलपुर ढाबे के पास रखा गया है।

देवेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने पेश किया 449 पन्नों का चालान

बलौदाबाजार। 10 जून को बलौदाबाजार में हुई आगजनी, तोड़फोड़ व हिंसक प्रदर्शन मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव व ओमप्रकाश बंजारे का चालान आज कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया। लगभग तीन महीने से जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी मानते हुए पुलिस ने 449 पेज का चालान पेश किया है। मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी। वहीं हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता अनादि शंकर मिश्रा ने बताया कि आज पुलिस ने चालान पेश किया है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि पुलिस की तरफ से कोई बड़ा साक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। न्यायालय ने 23 नवंबर को पुन: पेशी दिया है। वहीं विधायक देवेंद्र यादव की हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगी है, जिस पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी।

आपदा से निपटने रेलवे और एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल

दुर्ग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आज आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) कटक के साथ मिलकर आज बीएमवाई चरोदा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान रेल आपदा के दौरान निर्मित होने वाले कई तरह के हालातों से निपटने के लिए जवानों ने बचाव का पूर्वाभ्यास किया। रेलवे और एनडीआरएफ के इस संयुक्त मॉक ड्रिल के दौरान टीम ने ट्रेन में बम की सूचना, आगजनी और अन्य तरह के आपदा में फंसे हुए यात्रियों को बचाने का अभ्यास किया। इस दौरान एनडीआरएफ कटक के डिप्टी कमांडेंट कन्हैया योगी और रायपुर रेल मंडल के एडीआरएम बजरंग अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाले जवानों की हौसला अफजाई किया। इसके साथ ही सभी तरह के आपदा की स्थिति के लिए जवानों को हर तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए। कटक डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ कन्हैया योगी ने बताया इस तरह के अभ्यास से रेल आपदाओं से निपटने के लिए जवानों को तैयार किया जाता है।

बलौदाबाजार में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए भर्ती

बलौदाबाजार। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत लवन एकीकृत बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती होनी है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए तिल्दा आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-3 शामिल है। आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद के लिए आठवीं पास होना जरुरी है। खास बात यह है कि केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जमा करने के आखिरी तारीख 27 नवम्बर है। 27 नवंबर को शाम साढ़े पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पते पर आवेदन भेजें। अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक के जरिए जमा कराएं। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के लाइवलीहुड कॉलेज में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों से 30 नवम्बर तक आवेदन मंगाए गए हैं। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी आईटीआई गौरेला में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।

सड़क किनारे खड़े ट्रक को एंबुलेंस ने पीछे से मारी टक्कर

जगदलपुर। कोड़ेनार थाना क्षेत्र अंर्तगत शहर से 40 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 63 किलेपाल के पास गुरुवार की तड़के एक एंबुलेंस ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, हादसे में एंबुलेंस सवार डॉ. मनोज पांडे और ड्रेसर राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। एंबुलेंस सवार अन्य दो घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल परियोजना अस्पताल से एक मरीज को जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। मरीज को एंबुलेंस के माध्यम से लाया जा रहा था, जिसमें चालक, मरीज समेत एक डॉक्टर और ड्रेसर भी थे। तेज रफ्तार एंबुलेंस गुरूवार सुबह करीब 5 बजे के बीच किलेपाल में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि एंबुलेंस के परखच्चे उड़ गए। वहीं एंबुलेंस का चालक और मरीज घायल हो गया। जबकि सामने सीट में बैठे डॉक्टर और ड्रेसर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसकी जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर की मदद से एंबुलेंस को हटाया गया।

बैकुंठपुर जिला अस्पताल में एक्स रे हुआ महंगा

■ मरीजों को खर्च करने पड़ रहे ज्यादा पैसे

बैकुंठपुर। जिला अस्पताल में इन दिनों एक्स रे कराना काफी महंगा पड़ रहा है। पहले जिस एक्स रे के लिए 50 से 100 रुपये देने पड़ते थे अब उसके लिए 150 से 300 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

बैकुंठपुर जिला अस्पताल में आए दिन एक्सीडेंट या हड्डी के चोट के केस के चलते एक्स-रे कराने मरीज पहुंचते है। इन मरीजों को सामान्य एक्स रे का 50 रुपये और डिजिटल एक्स रे कराने का 100 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती थी लेकिन अब मरीजों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। अब सामान्य एक्से का 150 रुपये और डिजिटल एक्स रे का 300 रुपये देना पड़ रहा है।

जिला अस्पताल में सामान्य एक्स-रे 300 रुपए और डिजिटल एक्स-रे 450 रुपए में होता है। यानी जिला अस्पताल और प्राइवेट में कराए गए एक्स-रे में केवल 150 रुपए का अंतर है। ऊपर से 150 रुपए बचाने के लिए पहले पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगकर घंटो समय की बर्बादी होती है। इसके बाद एक्स-रे कक्ष के बाहर लाइन लगानी पड़ती है। सुविधाओं के नाम पर मरीजों से कहा जाता है कि वे आयुष्मान कार्ड का उपयोग करें। वहीं 59 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों के लिए शुल्क कम है।

एक्स रे का रेट बढ़ाने के मामले में बैकुंठपुर जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉ प्रशांत सिंह का कहना है कि अस्पताल में आयुष्मान से निशुल्क एक्स रे किया जा रहा है। 60 साल से ऊपर की आयु वर्ग वाले और स्कूली बच्चों का फ्री में एक्स रे किया जा रहा है। अस्पताल में एक्स-रे शुल्क 300 रुपए लिया जा रहा है इसके लिए जीवन दीप समिति से बात की जा रही है।

सीएमएचओ ने कहा कि प्राइवेट में 400 से 450 रुपए डिजिटल एक्स-रे के लगते हैं उससे तुलना की जाए तो अस्पताल में कम पैसे लिए जा रहे हैं। एक बार और जीवन दीप समिति से बात कर 50 रुपये और कम करने की कोशिश की जाएगी।

सक्रिय 1 नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर तथा अति-संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप नक्सली संगठन में सक्रिय 1 नक्सली सोड़ी माड़का पिता पाण्डू (मिलिशिया सदस्य, दुलेड़ आरपीसी) उम्र 34 वर्ष निवासी ताड़मेटला इत्तापारा थाना चिंतागुफा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत, प्रभारी नक्सल सेल एवं निरीक्षक सुजीत कुमार, 223 वाहिनी सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

धमतरी और मुंगेली से पकड़े गए 29 जुआरी

धमतरी/मुंगेली। धमतरी की बिरेझर पुलिस चौकी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग अलग अलग जगहों पर जुआ खेल रहे थे। पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। वहीं मुंगेली पुलिस ने भी लोरमी इलाके में कार्रवाई करते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों के पास से 1 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की है।

बिरेझर पुलिस को सूचना मिली थी कि चिरईया खार इलाके में दो जगहों पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी। दोनों जगहों पर कार्रवाई के दौरान कुल 18 लोग गिरफ्तार हुए। पकड़े गए लोगों के पास से नकदी करीब 1 लाख बरामद हुई। पकड़े गए लोगों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए जुआरियों का पुराना रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है।

एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने बताया 18 जुआरियो को ताश पत्ती खेलते पकड़ा है। जिनसे 1 लाख 3 हजार 50 रुपये और 2 बंडल ताश जप्त किये गए हैं। जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

लोरमी पुलिस ने भी जुए के फड़ पर दबिश देकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों के पास से 1 लाख 8 हजार की नकदी बरामद की गई है। पुलिस को खबर मिली की थी इलाके में जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलने के बाद एसपी भोजराम पटले स्थानीय पुलिस को मौके पर दबिश के लिए भेजा। पुलिस ने इलाके की घेरबंदी कर कुल 11 लोगों को जुआ खेलते दबोच लिया।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर समस्त जनजातीय समुदाय और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने जनजातीय समुदाय के पूर्वजों के अदम्य साहस, उनकी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्र निर्माण मे असाधारण योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि ये समुदाय हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं और उनकी संस्कृति एवं परंपराओं में प्रकृति के प्रति सम्मान और सामूहिकता का अनुपम भाव समाहित है। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश में विविधता से भरी हुई जनजातीय संस्कृतियाँ हैं, जिनसे हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण मूल्य सीखने को मिलते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन उन सभी महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अपने समुदाय की अस्मिता और देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणादायक योगदान दिया। हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। हम सब मिलकर अपने जनजातीय समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रहें। यही हमारे पूर्वजों के प्रति सच्चा सम्मान होगा।

साय को अमित ने लिखा पत्र, महतारी वंदन योजना की राशि बढ़ाने किया आग्रह

रायपुर। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। अमित जोगी ने अपने पत्र में कहा मुख्यमंत्री आधी आबादी, नारी शक्ति के लिए पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में लोकप्रिय योजना लाड़ली बहन, लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किया जाता है परंतु दुर्भाग्यवश छत्तीसगढ़ में बहनों को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह केवल 1000 रुपए की राशि प्रतिमाह प्रदान किया जाता है जो कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी, छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति और हमारी लाड़ली बहनों के साथ सौतेला व्यवहार और बहनों के साथ भेदभाव है। अमित जोगी ने मुख्यमंत्री साय से छत्तीसगढ़ की पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की लाड़ली बहनों को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए करने का आग्रह किया है।

सड़कों की जांच करने आएंगे राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक

रायपुर। मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ ग्रामीण

सड़क विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के निरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नवम्बर 2024 हेतु दौरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक राजू अजय कुमार, मोबाईल नंबर +91-94191-61196 छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा एवं बलरामपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं।

अधिकारी को उसी जगह पर दे दी पोस्टिंग जहां से वह हुआ था निलंबित

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में गजब का खेल चल रहा है। निलंबित अधिकारी को बहाल कर फिर पोस्टिंग दे दी, उसके बाद आदेश में संशोधन करते हुए वहीं फिर से वहीं पोस्टिंग दे दी, जहां से वे निलंबित हुए थे। बात हो रही है शिक्षा विभाग में अधिकारी हेमंत उपाध्याय की, जिन्हें अस्थाई रूप से बतौर प्रभारी संयुक्त संचालक सरगुजा में आगामी आदेश पर तक पदस्थ किया गया, जबकि उन्हें उसी पद से पदोन्नति, ट्रांसफर में आर्थिक अनियमितता करने की दोषी बताकर निलंबित किया गया था। मामले में अभी विभागीय जांच जारी है, उसके बावजूद पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री वर्मा धमतरी के समारोह में होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसामुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवम्बर 2024 को जिला मुख्यालय धमतरी में आयोजित की जाएगी। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व एवं आपदा तथा खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा उपस्थित रहेंगे।

हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण का निर्माण आज से

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण हेतु रिलीविंग गर्डर की लांचिंग के लिए 15, 16 एवं 17 नवंबर को ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के चलते कुछ यात्री गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

खाद्य मंत्री बघेल ने सूरजपुर से की धान खरीदी की शुरुआत

समिति प्रबंधकों को चेताया, मीडिया से जुड़े लोगों से कहा कि कही कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो उसे जरूर बताएं

सूरजपुर। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने सूरजपुर जिले से गुरुवार को प्रदेश में धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने समिति प्रबंधकों को आगाह करते हुए कहा कि अगर किसानों से सही व्यवहार नहीं किया, किसानों से धान की पलटी करवाई या उनसे धान को छल्ली लगवाया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला के प्रभारी व खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने समिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें धान बेचने के लिए एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। वहीं मीडिया से जुड़े लोगों से कहा कि कही कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो उसे जरूर बताएं।

इधर मंत्री टंकराम वर्मा ने आज सांकरा (तिल्दा) में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर अधिकारियों से अन्नदाताओं की सुविधा के लिए बारदानों की व्यवस्था, फड़, चबूतरा, पीने का पानी, बैठने की छायादार व्यवस्था इत्यादि करने के निर्देश दिए।

बता दें कि आज से राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जा रहा है। इस खरीफ

सीजन में धान बिक्री के लिए 27,01,109 किसानों ने पंजीयन कराया है, इनमें से 1,35,891 नए किसान शामिल हैं। कुल 34,51,729 हेक्टेयर रक्बे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है।

सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बड़े कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। इसके लिए 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। खरीदी सीजन में लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन एवं बड़े कृषकों को 3 टोकन की पात्रता होगी। धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा किए गए हैं।

विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है, जिसका नं। 0771-2425463 है। धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा समितियों में ''माइक्रो एटीएम'' की व्यवस्था भी दी जा रही है, जिससे कि किसानों को सुविधा हो।

राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है, एवं चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। मंडी विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है। मार्कफेड द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित कर राइस मिल एवं उपार्जन केन्द्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी।

इसके अलावा राज्य स्तर पर अलग-अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग करेंगे। विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य स्तरीय दल आबंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत भी कराया जाएगा।

दुर्ग में पहले दिन 1206 किसानों से 60 हजार क्विंटल धान की होगी खरीदी

दुर्ग। धान खरीदी की शुरुआत इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में शानदार तरीके से शुरु की गई है। कई खरीदी केंद्रों पर किसानों का स्वागत सत्कार किया गया। इस बार धान खरीदी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों की हमेशा से ये मांग रही है कि खरीदी केंद्रों पर वजन मशीन से किया जाए। इस बार सरकार ने वजन तौलने वाले कांटे हर खरीदी केंद्रों पर लगवाए हैं। इससे हिसाब रखना आसान होगा। किसानों को भी कोई दिक्कत नाप तौल को लेकर नहीं होगी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने धान खरीदी से पहले ही अधिकारियों को खरीदी से संबंधित कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। इस बार जिले में 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि सभी उपार्जन केन्द्रों में शुरुआती दिन में 1206 किसानों के टोकन काट गया है। पहले दिन किसानों से 60 हजार क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया सभी धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू और बारदाने दिए गए हैं। एसडीएम और नोडल अधिकारी इसकी लगातार निगरानी करते रहेंगे। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी की जायेगी। किसानों के खातों में तुरंत पैसे आ जाए इसके लिए माइक्रो एटीएम सभी केंद्रों में तैयार किए गए हैं। बैंको के एटीएम में लिमिट 20 की जगह अब 40 हजार रुपए की गई है।

कलेक्टर ने बताया कि किसानों को बारदाने की किल्लत महसूस न हो इसलिए 50 प्रतिशत पुराने और 50 प्रतिशत नए बारदाने केंद्रों तक उपलब्ध कराए गए हैं।

ईडी ने पूर्व सीएम के करीबी के खिलाफ दर्ज किया मामला

फर्जी बैंक खाता खुलवाकर पैसों के लेन-देन का है आरोप

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव के खिलाफ पीएमएलए और एफईओए के तहत मामला दर्ज किया है। इसके पहले तेलीबांधा थाने में केके श्रीवास्तव के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने के नाम से 15 करोड़ रुपए की ठगी करने का अपराध दर्ज किया गया था।

बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में पाया गया कि केके श्रीवास्तव ने दिल्ली और मुंबई में जोमैटो तथा स्विगी में काम करने वाले लड़कों के नाम से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर 500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। इस बात की जानकारी रायपुर पुलिस ने ईडी और आयकर विभाग को पत्र लिखकर दी थी।

मामले में अब ईडी ने रायपुर पुलिस की एफआईआर के आधार पर केके श्रीवास्तव के खिलाफ पीएमएलए 'धन शोधन निवारण अधिनियम' और एफईओए 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' के तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, केके श्रीवास्तव ने दिल्ली के रावत एसोसिएट के डायरेक्टर अर्जुन रावत को स्मार्ट सिटी लिमिटेड रायपुर में 500 करोड रुपए का ठेका दिलवाने के नाम से विभिन्न बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपए डलवाए थे। रावत एसोसिएट्स कंपनी- हाइवे कंस्ट्रक्शन, सरकारी ठेके बिल्डिंग निर्माण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम करती है।

कंपनी के डायरेक्टर की केके श्रीवास्तव से मुलाकात 2023 में आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन के माध्यम से हुई थी। राखड़ और फ्लाई ऐश का काम करने वाले केके श्रीवास्तव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी बता ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ लिया और काम नहीं दिलाया।

प्रार्थी ने पुलिस से की गई अपनी शिकायत में लिखा है कि केके श्रीवास्तव ने उन्हें रायपुर बुला प्रदेश के सबसे बड़े नेता से मिलवाया था। बड़े नेता ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा था कि केके भरोसे के आदमी है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन काम नहीं होने पर रकम वापसी के लिए तीन-तीन करोड़ के चेक दिए गए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए।

पुलिस के अपराध दर्ज करने की जानकारी लगते ही केके श्रीवास्तव परिवार के साथ फरार हो गया। पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए दस हजार रुपए का इनाम रख दिया गया। थाने में अपराध दर्ज होने के बाद रायपुर सत्र न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद केके श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

केके श्रीवास्तव के अधिवक्ता ने इसे धोखाधड़ी न मानते हुए आपसी लेनदेन का मामला बता जमानत देने का निवेदन किया था। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में गंभीर टिप्पणी की थी। पुलिस द्वारा पेश की गई तगड़ी केस डायरी और जमानत विरोध को देखते हुए श्रीवास्तव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब ईडी के द्वारा मामला दर्ज करने से केके श्रीवास्तव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ियों का चयन

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन ने राज्य के 9 खिलाड़ियों का चयन आगामी एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भाग लेने के लिए किया है। यह चैंपियनशिप 15 से 17 नवंबर 2024 तक गोवा के पेडम इंडोर स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसमें एशिया के कई प्रतिभाशाली एथलीट भाग लेंगे। इसमें दंतेवाड़ा जिले से भी 5 खिलाड़ी संदीप साह सीनियर वर्ग (70 किग्रा), आनंद ठाकुर सब जूनियर (45 किग्रा), पुष्पा नायक जूनियर (46 किग्रा),भावना निषाद सीनियर (40 किग्रा), नूपुर ठाकुर जूनियर (51.7 किग्रा),निरांजलि सोनी जूनियर (55 किग्रा) शामिल हैं।

इससे पहले भी इन सभी खिलाड़ियों ने नेपाल काठमांडू में आयोजित साऊथ एशियन चैंपियनशिप 2023 में भाग लिया था, जिसमें 4 खिलाड़ियों ने गोल्ड तथा 1 सिल्वर मेडल लेकर जीत दर्ज की थी। इन खिलाड़ियों का चयन थाई बॉक्सिंग इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में उनके बेहतरीन प्रदर्शन और थाई बॉक्सिंग इंडिया फेडरेशन के दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है। छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इन खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की सराहना की है और उन्हें चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

चैंपियनशिप में जाने से पूर्व सभी प्रतिभागी दंतेवाड़ा विधायक श्री चैतराम अटामी से मिले एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, श्री अटामी के द्वारा सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी गई, एवं अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया गया, साथ ही किसी भी प्रकार की आवश्यकता पडने पर जानकारी देने को कहा।

डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई महिला, शातिर ने झांसा देकर की 58 लाख की ठगी

रायपुर। डिजिटल अरेस्ट मामले में रायपुर के रेंज साइबर थाना ने बड़ी कार्रवाई की है। पंडरी में महिला से 58 लाख रुपये ठगने वाले एक आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से ठगी की रकम में से 9.50 लाख रुपये नगद, बैंक खाता, चेक बुक और मोबाइल जब्त किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्तियों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उसे आधार कार्ड के दुरुपयोग से 311 बैंक खाते खोलने का आरोप लगाया। आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर 24 घंटे व्हाट्सएप वीडियो कॉल में जुड़े रहने का दबाव बनाया और डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 58 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए रेंज साइबर थाना रायपुर को जांच सौंपी। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज साइबर थाना रायपुर को तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने एवं ठगी की रकम होल्ड जब्त करने के संबंध में निर्देश दिए। मामले में जांच के दौरान साइबर थाना की टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए आरोपी जसविंदर सिंह साहनी, निवासी राजनंदगांव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 9.50 लाख रुपये की नकदी, बैंक खाता, चेक बुक और मोबाइल बरामद की गई है।

दक्षिण विधानसभा में 50% वोटिंग को लेकर अजय चंद्राकर का बड़ा बयान, कहा-

मतदान अनिवार्य करने का लाना चाहिए कानून

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव में कम मतदान पर चिंता जताते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब अनिवार्य मतदान को लेकर कानून बनाना चाहिए। दरअसल बुधवार को दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रकिया चली, लेकिन वोटरों में उत्साह की भारी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से शाम 6 बजे तक 50.50 प्रतिशत ही मतदान दर्ज हुआ।

कम मतदान से कांग्रेस को जीत की उम्मीद पर चंद्राकर का तंज

कम वोटिंग से कांग्रेस को जीत की उम्मीद पर अजय चंद्राकर ने पर तंज कसा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक साल पहले भी सरकार बनाने में कॉन्फिडेंट थी। इसलिए भूपेश बघेल नया सीएम निवास को रोज देखने जाते थे। कांग्रेस ने केवल काम किया कि नया सीएम निवास जल्द बन जाए। 5 साल तक कांग्रेस का ध्यान इसमें ही था। कांग्रेस को सपने देखने से कौन रोक सकता है।

छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री साय आज धान खरीदी की शुरुआत कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पर दृढ़ता से अमल हो रहा है। 25 क्विंटल और 31 सौ रुपए की गारंटी पर अमल हो रहा है। समय में सही रूप में धान खरीदी होगी। समिति कर्मचारी की मांग को मुख्यमंत्री ने पूरा किया। किसानों के दाम को उचित मूल्य मिलेगा और प्रयास जोरदार है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

लाल आतंकी साया मिटाकर...

लोगों को उनकी संस्कृति से दूर किया, उनके समक्ष नए-नए आदर्श रखे, उनमें अपनी पहचान को लेकर भ्रम पैदा किया गया। कम्युनिस्ट आतंकवादियों ने ऐसे कई झूठे विमर्श स्थापित किए हैं। सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि माओवादी आदिवासी किसानों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि, सच यह है कि माओवादी ही जनजातीय लोगों का शोषण कर रहे हैं। उनके आतंकी लड़ाके गाँववालों से अपनी रसद वसूलते हैं। उन्हें आतंकियों को छिपाए रखने को विवश किया जाता है, और जो कोई मुखालफत करता है, वे उसकी क्रूरता से हत्या कर देते हैं। इसी तरह नक्सलियों को महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए लड़ने वाला बताया जा रहा है, जबकि जनजातीय महिलाओं का सर्वाधिक यौन शोषण माओवादी ही करते हैं। वे अपने संगठन में, अपनी कथित सेना में जिम्मेदारियाँ निभा रही महिलाओं को भी नहीं छोड़ते। अनेक आत्मसमर्पित माओवादियों ने इन अत्याचारों पर से पर्दा उठाया है। आदिवासियों के वनाधिकार के लिए लड़ाई के दावे का सच यह है कि जब केन्द्र सरकार वनाधिकार देने हेतु ड्रोन सर्वे के माध्यम से जमीन की डिजिटल मैपिंग कर रही है, तो ये माओवादी ही उसके विरोध में मिथ्यालाप कर रहे हैं क्योंकि इस मैपिंग से भारत के विरुद्ध जंग में बस्तर को अपना मुख्य अड्डा बनाने के कम्युनिस्ट आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। कुल मिलाकर, हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे कोई लोगों के लिए लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वे अपने भारत-विरोधी मंसूबों को पूरा करने के लिए दण्डकारण्य क्षेत्र में आए हैं। यह सच इन कम्युनिस्ट आतंकवादियों के दस्तावेज स्वयं ही उजागर कर देते हैं। सीपीआई (एम) का डॉक्यूमेंट 'स्ट्रैटेजी एण्ड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन' सबकुछ स्पष्ट कर देता है। यह जनजातीय समाज और किसानों के गुस्से से उपजा कोई स्वस्फूर्त आन्दोलन नहीं है। इन कम्युनिस्ट आतंकवादियों का तो संविधान और किसी तरह की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। इसे दुर्भाग्य कहें या फिर कम्युनिस्टों के दुष्प्रचार का प्रभाव कि आज सामान्य जनमानस में इस झूठ ने गहरी पैठ बना रखी है।

जनजातीय क्षेत्रों में पैदा की जा रही चुनौतियाँ- कम्युनिस्ट आतंकवादियों ने अब जनजातीय समाज पर अपनी पकड़ के कमजोर होने और सरकार द्वारा माओवाद-विरोधी अभियानों में आई तेजी से बौखलाकर कपट-युद्ध शुरू किया है। फलत: हमारे और हमारे जनजातीय बन्धुओं के समक्ष नई चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं। माओवादी अब यह झूठ भी फैला रहे हैं कि आदिवासी हिन्दू नहीं है। हिन्दू परम्परा का पालन करने पर लोगों को दण्ड दिया जा रहा है। इससे भारतीय समाज में भेद की एक नई रेखा के उपजने की आशंका है। इसके अलावा एक नया झूठ और स्थापित किया जा रहा है कि आदिवासी ही भारत के मूलनिवासी हैं, जो बाहरी लोगों द्वारा पीड़ित हैं। इससे भी समाज के विघटन का संकट हो सकता है। पत्थलगड़ी, पेसा, 5वीं व 6ठी अनुसूची, समान नागरिक संहिता और वनाधिकार कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा है। माओवादियों व चर्च का गठजोड़ भी जनजातीय क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अपने प्रभाव के क्षेत्रों में माओवादी राजनैतिक हत्याएँ तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ-साथ इन क्षेत्रों में वे अपना राजनैतिक नियंत्रण भी बढ़ा रहे हैं। इनके इकोसिस्टम द्वारा इन कम्युनिस्ट आतंकियों को राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पीड़ित-क्रान्तिकारी बताने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है।

जनजातीय समाज पर प्रभाव- चीन की तरह ही आतंकी तानाशाही की स्थापना की बदनीयती के साथ इन आतंकियों ने बस्तर की स्थिति भी ऐसी कर दी है; कि अब वहाँ न व्यक्ति और न ही अभिव्यक्ति का कोई महत्व है। मुँह खोलने की सजा मौत है। निरीह जनजातीय समाज के मन में उनकी ही चुनी सरकार के प्रति भय और आतंक के भाव इस सीमा तक भर दिए गए हैं कि वे लोग आज भी खाकी वर्दी देखकर छिप जाते हैं। महानगरों में एयर-कण्डीशण्ड कमरों में बैठे कुछ अप्रकट आतंकियों (या आम बोल-चाल के अर्बन नक्सलियों) ने लगातार इसे वंचितों का सरकार के प्रति विद्रोह बताने का दुष्चक्र चलाया है। और दुर्भाग्यवश, हमारे अकादमिक संस्थान भी नक्सल आन्दोलन कहकर इसे वंचित भारतीयों की व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में ही पढ़ा रहे हैं। जबकि बस्तर में अभी चल रही माओवादी हिंसा कोई वहाँ के जनजातीय लोगों की चलाई हुई नहीं है, बल्कि उन पर थोपी हुई है। सहअस्तित्व और सामूहिकता के उच्चादर्शों के साथ जीने वाले लोगों के मन में हिंसा और क्रूरता के बीज बोए जा रहे हैं। माओवादियों ने जनजातीय समाज के जीवन को इस सीमा तक प्रभावित किया है कि वे अब आत्मविस्मृत-से होते जा रहे हैं। जनजाति संस्कृति नष्ट की जा रही है, परम्पराएँ भ्रष्ट की जा रही हैं। मनौवैज्ञानिक रूप से उनका मूल स्वभाव बदल कर उनमें पीड़ित होने का भाव और जिहादी मानसिकता भरी जा रही है। पहले गाँव के विषय गायता और पुजारी सुलझाते थे, किंतु अब इसके लिए संघम सदस्य बैठता है। आज हमारे जनजाति बन्धु अपने पुरखों की जगह माओ, लेनिन, मार्क्स आदि को अपना आदर्श मानने को विवश हैं। रमणीय पर्यटन योग्य क्षेत्र की पहचान अब लाल आतंक बन गया है। हिंसा और अत्याचार के वातावरण में वहाँ बचपन मर रहा है। कुल मिलाकर कम्युनिस्ट आतंकवादियों ने जनजातीय समाज के जीवन को अपने उन्माद के नर्क में धकेल रखा है। ये आतंकवादी जनजातीय समाज और भारत के समक्ष नित-नई चुनौतियाँ खड़ी करते जा रहे हैं।

नक्सलमुक्त भारत और छत्तीसगढ़ के संकल्प पर हो रहा काम- लेकिन, ऐसा भी नहीं है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक विजन के साथ नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प के लिए सख्त फैसले लिए हैं। एक तरफ सुरक्षा बल और पुलिस के जवान माओवाद पर निर्णायक प्रहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएँ नक्सल प्रभावित गाँवों में संचालित की जा रही हैं। इनमें नियद नेल्लानार, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन), आदिवासी ग्रामीण आवास योजना, तेंदूपत्ता संग्रहण की मानक राशि में वृद्धि आदि उल्लेखनीय है। 16 फरवरी 2024 को शुरू की गई नियद नेल्लानार योजना के जरिए सुदूर नक्सल प्रभावित गाँवों में दो दर्जन से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद को समूल नष्ट करने को लेकर न सिर्फ गंभीर हैं बल्कि इसके लिए मोदी सरकार हर संसाधन मुहैया करा रही है। केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ समन्वित रणनीति बनाकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में ही बड़ा एन्टी नक्सल ऑपरेशन हुआ है, जिसमें सुरक्षाबलों ने 35 माओवादियों को ढेर किया है। पिछले नौ महीनों में 194 से अधिक माओवादी मारे गए हैं, 800 से ज्यादा नक्सलियो का गिरफ्तारियां हुई हैं और 738 नक्सालयों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षाबलों ने 10 माओवादी ऐसे मारे हैं जिनका छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में लम्बे समय से खौफ बना हुआ था। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है।

बस्तर शांति समिति की क्रांतिकारी पहल- एक तरफ केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकारों ने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ रखी है, वहीं दूसरी तरफ बस्तर शांति समिति ने क्रांतिकारी पहल करते हुए बस्तर के 50 नक्सल पीड़ित जनजातीय लोगों का जत्था लेकर नई दिल्ली में जाकर वामपंथी आतंकवाद के खिलाफ शंखनाद किया। नई दिल्ली जाकर नक्सल पीड़ितों ने मानवाधिकारवादियों से गुहार लगाई कि नक्सलियों के अधिकारों पर शोर मचाने वालों को जनजातियों के शांतिपूर्ण और आतंकमुक्त जीवन के अधिकारों की रक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। इस जत्थे ने अपने इस दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके अपनी आपबीती सुनाई। बस्तर शांति समिति के बैनर तले नक्सल पीड़ित आदिवासियों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया और वामपंथी उग्रवाद की अब तक उपजाऊ जमीन रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाकर भी नक्सली आतंक के खिलाफ शंख फूँका। बस्तर शांति समिति की यह पहल देशभर में चर्चा का बनी और मानवाधिकार के नाम पर नक्सलियों की ढाल बनते रहने वाले मानवाधिकारवादियों के पाखंड से देश रू-ब-रू हुआ।

सुपरिणाम सामने आने लगे-इन तमाम प्रयासों के सुपरिणाम भी सामने आने लगे हैं। अभी हाल ही बस्तर के ही नारायणपुर के नक्सल प्रभावित गारपा ग्राम के वे लगभग 40 परिवार, जो नक्सलियों के भय से नारायणपुर के ही गुडरीपारा में रह रहे थे, वापस अपने गाँव रहने के लिए लौट आए हैं, जिन्हें नक्सलियों ने करीब दो दशक पहले गाँव से बेदखल करते हुए भगा दिया था। यदि यह क्रम चलता रहा तो यकीनन जनजातीय समाज का खोया स्वाभिमान लौटेगा और वह अपने गौरवशाली अतीत के साथ-साथ विकास की मुख्यधारा से भी जुड़ेगा। इससे जनजातीय समाज के प्रति व्याप्त विकृत धारणाओं का शमन भी होगा और सम्पूर्ण हिन्दू समाज एकजुट होकर आतंक, भय, विवशता के चंगुल से मुक्त जनजातीय समाज के साथ विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार भी करेगा। यही जनजाति गौरव दिवस की सार्थकता होगी।

क्या अपनी धार खो रही हैं लिबरल ताकतें?

नरेन्द्र नाथ

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप की जीत के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में उदारवादी दलों के नैरेटिव और जनता से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के दौरान वहां दोनों उम्मीदवारों ने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन चुनाव परिणाम ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हैरिस ज्यादातर लोगों तक अपनी बात प्रभावी अंदाज में नहीं पहुंचा सकीं। चुनाव बाद आए आंकड़े बताते हैं कि रिपब्लिकन नेता ट्रंप को महज दक्षिणपंथी खेमे के नहीं बल्कि उन तबकों के भी अच्छे खासे वोट मिले, जिनके बारे में अनुमान था कि वे लिबरल ताकतों का समर्थन करेंगे। लैटिन अमेरिकी मूल के लोगों ने ही नहीं, अश्वेत पुरुषों ने भी ट्रंप को कमला हैरिस से अधिक वोट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने वोट देकर ट्रंप की नीतियों का सपोर्ट किया। उनके सामने 'आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे' वाली स्थिति थी। अधिकतर अमेरिकी मानते हैं कि उनका मौजूदा जीवन चुनौतियों से भरा है। पिछले कुछ सालों में महंगाई ने उनके घरों का बजट बिगाड़ दिया है। उनके लिए नौकरी के मौके कम हुए हैं। वे आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे सबसे पहले इन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। उन्हें लगा कि कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स ने अपने पूरे चुनाव प्रचार से इन मुद्दों को या तो अलग रखा या इन पर अपने स्टैंड को स्पष्ट नहीं किया। इन वोटरों ने वैचारिक तौर पर कमला हैरिस के साथ दिखने की बात कही, लेकिन आखिरकार वोटिंग पैटर्न अलग रहा। जानकारों के मुताबिक, यह सामान्य ट्रेंड रहा है कि जब लोगों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वे तात्कालिक तौर पर अपनी आयडियॉलजिकल लड़ाई को विराम दे देते हैं। वे पहले अपने जीवन की प्राथमिक दिक्कतों को दूर करने का रास्ता तलाशते हैं। अमेरिका में इस बार के चुनाव में ऐसा ही हुआ। कई कोर डेमोक्रेट्स समर्थकों ने भी इस चुनाव में ट्रंप को वोट दे दिया। वे तत्काल अपने जीवन में आर्थिक चुनौतियों के मोर्चे पर हल चाहते थे और उन्हें लगा कि कमला हैरिस के लिए इसे दूर करना प्राथमिकता में नहीं है। अमेरिका में जो हुआ वह हाल के वर्षों में ग्लोबल ट्रेंड के रूप में भी उभरा है। लिबरल राजनीति कहीं न कहीं अपने नैरेटिव को आम जन की जरूरतों, उनकी अपेक्षाओं के साथ कनेक्ट करने में विफल साबित हो रही है। इसका मूल कारण है आयडियॉलजिकल मुद्दों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर इसी के इर्द-गिर्द चुनाव लड़ने की उनकी रणनीति। इस कवायद में वे जनता को यह बताने-समझाने में या तो देरी कर जाते हैं या कहीं न कहीं विफल हो जाते हैं कि बुनियादी मुद्दों को सुलझाने के लिए उनके पास भी कोई ब्लू प्रिंट है। यह सही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अबॉर्शन एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया था। कमला हैरिस और उनकी टीम ने इसे प्रमुखता से उठाया भी। वह इस उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में थीं कि इस पर उन्हें सभी महिलाओं का समर्थन मिलेगा। महिलाओं ने इस मुद्दे पर कमला हैरिस को मुखर समर्थन दिया भी। लेकिन जैसा कि ग्राउंड जीरो पर महिलाओं से हुई मीडिया की बातचीत में स्पष्ट हुआ, उनके लिए यह एक मुद्दा तो जरूर था, लेकिन सिर्फ यही मुद्दा नहीं था। एक महिला ने कहा, 'हमें अपने बच्चों की शिक्षा, घर के बढ़ते बजट, कम होते नौकरी के मौके के बारे में भी तो सोचना होगा। ये मुद्दे भी तो हमारे ही हैं।' ऐसी सोच वाली कई महिलाओं ने अबॉर्शन के मुद्दे पर कमला हैरिस को समर्थन दिया, लेकिन वोट नहीं। कमला हैरिस यहीं चूक गईं। शानदार जीत के बावजूद ट्रंप की आगे की राह आसान नहीं है। लिबरल नैरेटिव में आई शून्यता का लाभ उठाकर उन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उनके सामने उन वादों पर अमल करने की चुनौती होगी। उनके पास कोई हनीमून पीरियड नहीं होगा। आर्थिक मोर्चे और रोजगार जैसे मुद्दों पर आम लोगों को राहत देने के साथ ही उन पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाने का भी दबाव होगा। ध्यान रहे, ये दोनों काम साथ-साथ करना बहुत कठिन होगा। दोनों मकसद परस्पर विरोधी दिशा के हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि ट्रंप को इस चुनाव में जनादेश वास्तव में देश की आर्थिक सुधारने के लिए मिला है। उन्होंने कई ऐसे वादे किए हैं, जिन्हें पूरा करना खासा मुश्किल साबित हो सकता है। कुल मिलाकर डॉनल्ड ट्रंप की जीत ने ग्लोबल राजनीति में नई बहस की शुरुआत की है और उदारवादी राजनीतिक दलों के आगे के रोडमैप पर सवाल उठा दिया है। इसका जवाब काफी हद तक आने वाले समय के घटनाकम पर निर्भर करेगा।

वोटिंग से पहले एमवीए के दौर की घटनाएं सोशल मीडिया पर

अभिनय आकाश

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यहां वक्त कभी थमता नजर नहीं आता है। 24 घंटे सातों दिन भागने वाला शहर मुंबई ने तरक्की और भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ ही कई सियासी दांव पेंचों का दौर भी देखा है। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भारत का सबसे अमीर राज्य है। बड़े बिजनेस, बॉलीवुड का ग्लैमर्स तड़का और बड़ी चीनी सहकारी समितियों का घर जो किसी जमाने में ग्रैंड ओल्ड पार्टी का मजबूत दुर्ग हुआ करता था। लेकिन हिंदुत्व की धार के सहारे राज्य में भगवा लहराया और नए समीकरण के सहारे नए प्रकार का गठबंधन अस्तिव में आया। बहरहाल, 23 नवंबर को महाराष्ट्र की सत्ता में कौन आएगा? ये सवाल महाराष्ट्र और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स ने ज़रूर जानना चाह रहा होगा। इसका जवाब तो 20 नवंबर को 288 सीटों पर वोटिंग के बाद रिजल्ट आने पर पता चलेगा। लेकिन आज आपको महाराष्ट्र की सियासत के साथ ही सोशल मीडिया पर नेटिज़न्स की तरफ से शेयर किए गए महाविकास अघाड़ी के दौर के दौरान हुए कुछ घटनाक्रम के बारे में बताएंगे।

कांग्रेस का स्वर्णिम युग

आजादी के बाद के वर्षों में कांग्रेस बॉम्बे राज्य में एकमात्र प्रमुख राजनीतिक ताकत थी- और 1951-52 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में, उसने विधानसभा की 317 सीटों में से 269 सीटें जीतीं। कुल मिलाकर 268 निर्वाचन क्षेत्र थे - कुछ निर्वाचन क्षेत्रों ने उस समय एक से अधिक सदस्यों को विधायिका में भेजा था। नासिक-इगतपुरी देश में एकमात्र तीन सदस्यीय (एक सामान्य श्रेणी, एक एससी और एक एसटी) विधानसभा क्षेत्र था। मोरारजी देसाई 1952 में बॉम्बे के पहले मुख्यमंत्री बने। 1955-56 में जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन उग्र हुआ, तो बॉम्बे (मुंबई) शहर में पुलिस गोलीबारी में 100 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए। तीव्र आलोचना का सामना करते हुए, वलसाड के एक गुजराती मोरारजी को दिल्ली ले जाया गया और 1956 में केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया। उनकी जगह सतारा के विधायक यशवंतराव चव्हाण ने ली। चव्हाण के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 1957 के विधानसभा चुनाव में 396 सीटों (339 निर्वाचन क्षेत्रों) में से 234 सीटें जीतीं। 1962 के विधानसभा चुनाव में, जो महाराष्ट्र के निर्माण के बाद पहली बार हुआ, कांग्रेस ने 264 सीटों में से 215 सीटें जीतीं और मारोत्राव शंभशियो कन्नमवार मुख्यमंत्री

बने। अगले वर्ष उनके असामयिक निधन के बाद, मुख्यमंत्री पद वसंतराव नाइक को सौंप दिया गया, जो लगभग 12 वर्षों तक इस पद पर बने रहे।

हिंदुत्व का उदय

इसी माहौल में राज्य में हिंदू दक्षिणपंथ की ताकत बढ़ी। राजनीतिक कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे ने 1966 में मराठी राष्ट्रवादी शिव सेना का गठन किया था, और पार्टी को 1972 में अपना पहला विधायक मिला था। अपने शुरुआती वर्षों में शिव सेना वसंतदादा पाटिल जैसे लोगों के करीब थी; हालाँकि, 1980 में भाजपा के जन्म के बाद, दोनों पार्टियाँ स्वाभाविक सहयोगी के रूप में एक साथ आ गईं। 1985 के विधानसभा चुनाव में, भाजपा ने 16 सीटें जीतीं, जबकि सेना ने अपना खाता नहीं खोला। हालाँकि, 1990 तक, दोनों पार्टियों की सीटें क्रमश: 52 और 42 सीटों तक बढ़ गईं। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद बॉम्बे (मुंबई) में हुए सांप्रदायिक दंगों और सिलसिलेवार विस्फोटों ने हिंदुत्व दक्षिणपंथ के उदय को और बढ़ावा दिया। 1995 में सेना-भाजपा गठबंधन क्रमश: 73 और 65 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सत्ता में आया। सेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने। यह जीत सेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और भाजपा के उभरते सितारे प्रमोद महाजन से प्रेरित थी। कांग्रेस ने 80 सीटें जीतीं। 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद जोशी केंद्र में चले गए और ठाकरे ने उनके उत्तराधिकारी के लिए नारायण राणे को चुना। 1999 में, साढ़े चार साल के सेना-भाजपा शासन के बाद, राज्य में समय से पहले चुनाव कराए गए।

एमवीए सरकार के दौरान की क्यों दिलाई जा रही याद

महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान की याद दिलाई जा रही है। कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि एमवीए के लौटने पर सेंसरशिप और मनमानी गिरफ़्तारियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। नेटिज़न्स ने संकेत दिया कि अगर एमवीए वापस आता है महाराष्ट्र में सत्ता, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ लक्षित हमलों की एक श्रृंखला जारी रहेगी। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में से एक मराठी अभिनेत्री केतकी चितले का था, जिन्हें एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ एक पोस्ट साझा करने के बाद लगभग 40 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। एक यूजर से पोस्ट में कहा कि ये वीडियो मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले के जेल से रिहा होने का है। उनके खिलाफ 22 एफआईआर दर्ज की गईं। वांछित अपराधी की तरह गिरफ्तार किया गया। 40 से अधिक दिन जेल में बिताए। और क्यों? शरद पवार की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर एक कविता साझा करने के लिए? क्या महाराष्ट्र फिर से इसके लिए तैयार है? नेटिज़न्स द्वारा साझा किया गया एक और वीडियो रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी का था, जिन पर उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान दो लोगों ने हमला किया था। एक यूजर ने संकेत देते हुए कहा कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अर्नब गोस्वामी के विच हंट को मत भूलिए अगर एमवीए सत्ता में आती है तो राज्य को आने वाले समय में ऐसे और हमलों की उम्मीद करनी चाहिए।

अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी

22 और 23 अप्रैल 2020 की मध्यरात्रि को, रात 10 बजे की बहस के बाद अपने नियमित एडिट कॉल के बाद, अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी घर वापस जा रहे थे, तभी दो बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर हमला किया था। हमलावरों ने अर्नब गोस्वामी की कार रुकवाने के लिए उनकी कार के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी और फिर उन पर हमला कर दिया। अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी बाल-बाल बच गये। हालांकि, हमलावरों ने कार पर हमला करने और शीशे तोड़ने की कोशिश करने के बाद कार पर स्याही भी फेंकी। पब्लिक टीवी के मुताबिक, गुंडों ने कबूल किया कि वे कांग्रेस से थे और हमला गोस्वामी के आवास से केवल 500 मीटर की दूरी पर हुआ। इसके अलावा, गोस्वामी के खिलाफ एक लक्षित विच-हंट में एमवीए नियम के तहत मुंबई पुलिस उनके आवास पर पहुंची। मुंबई पुलिस ने 2018 के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये मामला पहले ही बंद हो चुका था।

2020 में पालघर साधु की पीट-पीट कर हत्या

एमवीए सरकार के शासन के दौरान पालघर जिले में हिंदू साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या जैसी कई क्रूर घटनाएं सामने आईं। 16 अप्रैल 2020 को जूना अखाड़े से जुड़े दो साधु, 70 वर्षीय कल्पवृक्ष गिरि महाराज और 35 वर्षीय सुशील गिरि महाराज, अपने ड्राइवर 30 वर्षीय नीलेश तेलगाडेरे के साथ एक और साधु को समाधि देने के लिए मुंबई से जा रहे थे। गडकचिंचले गांव में 100 से ज्यादा लोगों की जंगली और उन्मादी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझ लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस का दावा है कि 70 वर्षीय व्यक्ति को बचाने के लिए मौके पर पहुंची उनकी टीम भी हिंसक भीड़ के हमले की चपेट में आ गई। लेकिन बाद में ऐसे वीडियो सामने आए जिसने पुलिस के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें देखा गया कि साधु पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। इसके बाद भीड़ ने पुलिसकर्मियों के सामने ही उन्हें पीट-पीटकर मार डाला। बाद में यह भी बताया गया कि साधुओं की हत्या जानबूझकर और राजनीति से प्रेरित हो सकती है। इसमें ईसाई मिशनरी संगठनों, कुछ स्थानीय एनसीपी नेताओं और वामपंथियों की संलिप्तता का भी संदेह था। हालाँकि, शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने इस घटना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और दावा किया कि राज्य ने कभी भी किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटना नहीं देखी है।

कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण पर बुलडोजर

सितंबर 2020 में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने उनके मुंबई स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण को लेकर 24 घंटे में दूसरा नोटिस भेजा। इसके कुछ देर बाद ही बीएमसी की एक टीम बुलडोजर, क्रेन और हथौड़े लेकर पहुंच गई और ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दफ्तर तोड़े जाने को लेकर कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि मणिकर्णिका फिल्म्ज में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई, यह मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है, आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा राम मंदिर फिर टूटेगा मगर याद रख बाबर यह मंदिर फिर बनेगा यह मंदिर फिर बनेगा, जय श्री राम।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्याय:

गतांक से आगे...

वामनपुराण- (क) त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुख:। (मत्स्य 53 । 44) (ख) पुलस्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने। (नारदोक्त सूची)

अर्थात्- वामनपुराण ब्रह्मा ने पुलस्त्य को, पुलस्त्य ने नारद को सुनाया।

वाराहपुराण- तत्रादौ शुभसम्वाद: स्मृतो भूमिवराहयो:। (नारदोक्तसूची)

अर्थात् - वाराहपुराण वाराह रूपी विष्णु ने भूमि के प्रति कथन।

मत्स्यपुराण- मनुमत्स्य सुसम्वाद:। (तारद्रोक्तसूची)

अर्थात् - मत्स्यपुराण मत्स्यावतारधारी विष्णु ने मनु के प्रति कथन किया।

कूर्मपुराण- माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दन:। (मत्स्य 53 । 47)

अर्थात- कूर्मपुराण कूर्मावतारधारी विष्णु ने कथन किया।

ब्रह्माण्डपुराण- ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकृत्याब्रवीत्पुन:। (मत्स्य 53 । 55)

इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि पुराणों के आदिम वक्ता- ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्कन्द, पराशर, अग्नि, सार्वाण, मार्कण्डेय और सनकादि ये सब हैं, तथा आदिम श्रोता ब्रह्मा, मरीचि, वायु, गरुड़, नारद, वशिष्ठ, मनु, जैमिनि, पुलस्त्य, भूमि आदि हैं। इन सबके पुरातन सम्वादों को ही वेदव्यास जी ने विगत द्वापर के अन्त में क्रमबद्ध किया है।

इस अध्याय का सारांश यह है कि जिस समय ऋषियों ने अपने शिष्यों को मन्त्रोपदेश करना आरम्भ किया था, उस समय मन्त्रोपदेश से पूर्व विनियोग अवश्य बताया था।

क्रमश: ...

बिरसा मुंडा हैं पृथ्वी के पिता एवं आदिवासियों के मसीहा

ललित गर्ग

'धरती आबा' यानी पृथ्वी के पिता के नाम से जाने वाले आदिवासी जनजीवन के मसीहा एवं भगवानतुल्य बिरसा मुंडा का 149वां जन्मोत्सव 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने न केवल अपनी प्रकृति, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासी बेल्ट में बंगाल प्रेसीडेंसी (अब झारखंड) में आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने अनूठे कार्यों, अवदानों एवं व्यापक सोच से राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान किया, कठोर संघर्षों से लोहा लिया। बिरसा मुंडा एक युगांतरकारी शख्सियत थे, उन्होंने

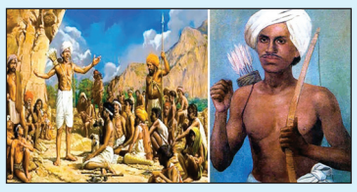

आदिवासी जनजीवन के कल्याण एवं उत्थान के लिये बिहार, झारखंड और ओडिशा में जननायक की पहचान बनाई। वे महान् धर्मनायक थे, तो प्रभावी समाज-सुधारक थे। वे राष्ट्रनायक थे तो जन-जन की आस्था के केन्द्र भी थे। सामाजिक न्याय, आदिवासी संस्कृति एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में उनके अनूठे एवं विलक्षण योगदान के लिये न केवल आदिवासी जनजीवन बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति सदा उनकी ऋणी रहेगी।

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को रांची जिले के उलिहतु गाँव में हुआ था। उनके पिता, चाचा, ताऊ सभी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। बिरसा के पिता सुगना मुंडा जर्मन धर्म प्रचारकों के सहयोगी थे।

भारत के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे आदिवासी नायक हैं जिन्होंने झारखंड में अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आदिवासी समाज की दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। अंग्रेजों द्वारा थोपे गए काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसत में डाल दिया। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके-सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। बिरसा जानते थे कि आदिवासी समाज में शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, अंधविश्वास है। बलि प्रथा पर भरोसा है, हड़िया कमजोरी है, मांस-मछली पसंद करते हैं। समाज बंटा है, लोगों के झांसे में आ जाते हैं। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं, तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। इन समस्याओं के समाधान के बिना आदिवासी समाज का भला नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने एक बेहतर नायक और समाज सुधारक की भूमिका अदा की। अंग्रेजों और शोषकों के खिलाफ संघर्ष भी जारी रखा। उन्हें पता था कि बिना धर्म के सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। इसलिए बिरसा ने सभी धर्मों की अच्छाइयों से कुछ न कुछ निकाला और अपने अनुयायियों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया।

ईरान को बुरे सपने आ रहे होंगे

सुरेंद्र कुमार

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार (लगातार नहीं) जीत दर्ज कर डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास तो रचा ही है, वह ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ऐसा करने वाले अमेरिका के पहले नेता भी बन गए हैं। तमाम कानूनी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने जिस महानतम ढंग से राजनीतिक वापसी की है, वैसा सदियों में शायद एक बार ही होता है। ट्रंप की धमाकेदार जीत (हालांकि मीडिया का एक वर्ग लगातार कह रहा था कि कांटे की टक्कर होगी) न केवल उनके एक राजनीतिज्ञ और नेता के रूप में, बल्कि विपक्षी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूरे अमेरिकी समाज के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। ट्रंप पर अस्थिरता, खराब आचरण, आक्रामक भाषा का प्रयोग और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन जैसे आरोप लगते रहे हैं, इसके बावजूद वह निस्संदेह एक करिश्माई नेता हैं, जिनके पास गहरा आत्मविश्वास, दृढ़ता और अपने समर्थकों को प्रेरित करने की गजब क्षमता है।

नवंबर, 2020 में मिली हार के बावजूद, उन्होंने यह कहना जारी रखा कि चुनाव में धांधली हुई थी और अदालती मामले उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश हैं। दो महाभियोग, 24 घोर आपराधिक मामलों के आरोप, सेक्स स्कैंडल, वर्गीकृत दस्तावेजों के अनधिकृत हस्तांतरण के आरोपों के बावजूद, ट्रंप झुके नहीं, उन्होंने तमाम बाधाओं का सामना करते हुए लड़ना जारी रखा और अंतत: जीत हासिल की। इन सबसे उनकी लोकप्रियता और उनके कट्टर समर्थकों पर उनकी जादुई पकड़ कम नहीं हुई।

दक्षिण एशियाई देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे पास ऐसी महिला नेता रही हैं, जिन्होंने अपने देश का वर्षों तक नेतृत्व किया।

पश्चिमी दुनिया में भी कई महिला नेताओं ने अपनी सरकारों की कमान संभाली है, लेकिन अमेरिका में नहीं। कमला हैरिस को दोहरी बाधा का सामना करना पड़ा, एक तो वह महिला हैं, दूसरा अश्वेत, एशियाई और कैरेबियाई मूल की हैं। दस सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस में कमला एकदम विजेता बनकर उभरीं। उन्होंने बिना आपा खोए सभी जवाब बड़ी ही संजीदगी के साथ दिए और ट्रंप की तरह आप्रवासियों को कुत्ता-बिल्ली और जानवर खाने वाला बताने जैसी अप्रिय भाषा का इस्तेमाल भी नहीं किया। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने, विभाजनकारी मानसिकता को नकारने और बेहतर भविष्य के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने महिलाओं के गर्भपात अधिकार के लिए झंडा उठाया, अति धनाढ्यों पर कर लगाने तथा कम आमदनी वालों, मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायों और दैनिक वेतनभोगियों की मदद करने का वादा किया था। उन्होंने निश्चित क्षेत्रों की यूनियनों का समर्थन भी किया। लेकिन चुनाव परिणामों ने बता दिया कि उनकी आदर्शवादी बातें मतदाताओं को ज्यादा रास नहीं आईं। दूसरी ओर, ट्रंप के समर्थकों ने लोकतांत्रिक मानदंडों पर उनकी सभी गलतियां माफ कर दीं।

कमला की हार में योगदान देने वाले कई कारण रहे। कमला की हार का सबसे बड़ा कारण तो राष्ट्रपति बाइडन थे। वह बेमन से राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हुए और कमला का समर्थन तब किया, जब काफी देर हो चुकी थी। हैरिस को चुनाव अभियान के लिए करीब तीन महीने का समय मिला, जो एक तरह से समय के विपरीत दौड़ लगाना था। चालीस फीसदी रेटिंग के साथ बाइडन अलोकप्रिय राष्ट्रपति थे। बाइडन की सभी सत्ता विरोधी लहरों ने कमला के जहाज को डुबो दिया। जब उनसे पूछा गया कि वह बाइडन से अलग क्या करेंगी, तो कोई प्रभावी जवाब नहीं दे सकीं। यद्यपि वृहद स्तर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर कर रही है, महंगाई घटी है, बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन भवन निर्माण लागत और किराने की बढ़ती कीमतों ने जमीनी स्तर पर उनको नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर, ट्रंप द्वारा आप्रवासियों को दुष्कर्मी, अपराधी और स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनने वाला बताया गया, जिससे मतदाताओं के मन में आप्रवासियों को लेकर डर का माहौल निर्मित हुआ।

डेमोक्रेटिक पार्टी ने सामान्य कमेरे वर्ग की नब्ज पर अपनी पकड़ खो दी। ओपरा विन्फ्रे, लेडी गागा, बियॉन्सी, जेनिफर लोपेज और टेलर स्विफ्ट समेत अन्य हॉलीवुड हस्तियां भी इस वर्ग को प्रभावित नहीं कर सकीं और हैरिस के खिलाफ मतदान किया। जबकि श्वेत और अश्वेत, पुरुष मतदाताओं ने ट्रंप को करीब 54 फीसदी वोट दिए। हैरिस के लिए लातिन और भारतीय अमेरिकियों का समर्थन भी घट गया। इस्त्राइल-हमास-हिजबुल्ला-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से निपटने में नाकामी, विशेष रूप से गाजा में हजारों फलस्तीनियों की हत्या ने अरब अमेरिकियों को नाराज किया और उन्होंने हैरिस के विरोध में मतदान किया। हालांकि महिलाओं ने उन्हें वोट दिए, लेकिन महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर हैरिस का जोर बाजी पलटने वाला साबित नहीं हुआ।

सभी आयातों पर ट्रंप द्वारा दस से बीस फीसदी टैरिफ लगाने और आप्रवासियों के एच1बी वीजा पर सख्ती से भारत भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के अच्छे रिश्ते यहां काम आ सकते हैं। वहीं, पेरिस जलवायु समझौते से ट्रंप की संभावित वापसी एक झटका होगी। चीन के साथ उनका टैरिफ युद्ध चीन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बुरा होगा। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखते हुए रूस ने कुछ राहत की सांस ली होगी और उम्मीद है कि यूक्रेन के साथ युद्धविराम का रास्ता खुलेगा। लेकिन ट्रंप की इस्त्राइल समर्थक नीतियों को देखते हुए लेबनान और गाजा में युद्धविराम की संभावना कम दिखती है। लेकिन वह समझते हैं कि उनके द्वारा समर्थित अब्राहम समझौते?(अरब-इस्त्राइल सामान्यीकरण)?का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि वह पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त नहीं करा देते। अमेरिका प्रथम की नीति के तहत ट्रंप के आने से डब्ल्यूटीओ व नाटो को झटका लग सकता है, तो ईरानी नेतृत्व को बुरे सपने आ रहे होंगे। जीत के बाद दिए गए ट्रंप के भाषण वाले मंच पर एलन मस्क की मौजूदगी कॉरपोरेट जगत पर भी असर डाल सकती है। खैर देखना होगा कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के अपने बहुप्रचारित संदेश पर ट्रंप कितने खरे उतरते हैं।

आज का इतिहास

1939 दक्षिण गुवानगक्सी की लड़ाई शुरू हुई।
1943 हेनरिक हिमलर द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, सभी जिप्सी के साथ-साथ मिश्रित जिप्सी रक्त के साथ यहूदियों के साथ एकाग्रता में रखा जाना चाहिए।
1943 होलोकॉस्ट-हेनरिक हिमलर ने आदेश दिया कि रोमियों को यहूदियों के समान स्तर पर रखा गया था और उन्हें एकाग्रता शिविर में रखा गया था।
1948 लुई स्टीफन सेंट लॉरेंट कनाडा के 12 वें प्रधानमंत्री बने।
1955 पोलैंड और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
1956 मध्य पूर्व तकनीकी विश्वविद्यालय तुर्की के अंकारा में स्थापित किया गया।
1959 अमेरिका के कंसास के होल्कम में दो लोगों ने एक परिवार की हत्या कर दी; घटनाओं ने ट्रूमैन कपोट के गैर-काल्पनिक उपन्यास इन कोल्ड ब्लड के विषय को सही अपराध शैली के रूप में काम किया।
1961 संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई।
1971 इंटेल ने दुनिया की पहली माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 रिलीज़ किया।
1971 इंटेल ने दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च किया।
1971 विश्व की पहली व्यावसायिक पूर्ण केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) एक चिप पर सिंगल-चिप माइक्रोप्रोसेसर 4004 का इंटेल द्वारा अनावरण किया गया है।
1973 जर्मनी में एक रेस्तरां के मालिक की बेटी का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन उसे रिहा करने के लिए एक मिलियन डॉलर से अधिक की फिरौती देने के बाद वापस नहीं लौटा।
1978 मक्का से इंडोनेशिया ले जा रहा एक विमान श्रीलंका में हादसे का शिकार हो गया। जिसमें 183 लोगों की मौत हुई।
1983 साइप्रस के उत्तरपूर्वी हिस्से पर स्थित तुर्की साइप्रियोट्स को तुर्की गणराज्य नॉर्दर्नकिप्रस के नाम से जाना जाने वाला एक नया राज्य बनाने की घोषणा करता है, जो वर्तमान में केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है।

जिम्मेदारी से बचने के लिए फारूख अब्दुल्ला ने छोड़ा शगूफा

योगेंद्र योगी

जम्मू-कश्मीर में सत्तारुढ़ नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवादी घटनाओं पर एक आश्चर्यजनक बयान दिया है। अब्दुल्ला ने बडगाम, बांदीपुरा में और श्रीनगर में आतंकी घटनाओं को लेकर कहा है कि इसमें उन्हें साजिश की बू आती है। उन्होंने कहा कि क्या कोई एजेंसिया तो नहीं है इन हमलों के पीछे जो उमर अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभवी राजनेजा फारूक के इस बयान से फरेबी मासूमियत झलकती है। एक ऐसा शख्स जिसने पूरा जीवन राजनीतिक के दावपेच में बिताया और वोट बैंक के भय से खुल कर कभी भी आतंकियों और पाकिस्तान की निंदा नहीं, वह सवाल उठा रहा है कि आतंकी घटनाओं की जांच हो कि इसमें कोई एजेंसियां तो शामिल नहीं हैं।

87 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला करीब 50 से अधिक वर्षों से राजनीति में हैं। वे केंद्र में मंत्री और जम्मू-कश्मीर में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ से ऐसे बचकाने बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या अब्दुल्ला इतने भोले हैं कि उन्हें पता नहीं है कि ये हमले कौन और क्यों करवा रहा है। इससे पहले इन्हीं अब्दुल्ला ने हमले करवाने के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाया था और यहां तक कहा था कि जम्मू-कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सीनियर अब्दुल्ला को अब इन हमलों में पाकिस्तान के अलावा किसी ओर पर शक होने लगा है।

दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने जब सत्ता संभाली थी तभी पिता-पुत्र को इस बात बखूबी अंदाजा था कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं को रोकना आसान काम नहीं हैं। सत्ता में आने से पहले दोनों ऐसी वारदातों का ठीकरा केंद्र पर फोडने में कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। इस प्रयास में आम नागरिकों के अलावा सैकड़ों सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। तब अब्दुल्ला पिता-पुत्र ने यह सवाल नहीं उठाया है। इसके विपरीत इन आतंकी घटनाओं को नेशनल कांफ्रेंस की सरकार को अस्थिर करने के चश्मे से देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इन्हीं पिता-पुत्र ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बड़ा हो-हल्ला मचाया था। यहां तक कि पिछले महीने हुए जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में इसे वापस लाने का वादा किया गया था।

पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला ने ही भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका दिया है। पाकिस्तान भी धारा 370 की बहाली की मांग करता आ रहा है। अब्दुल्ला और पाकिस्तान के सुर एक ही हैं। अब्दुल्ला ने यह मांग दोहरा कर एक तरह से पाकिस्तान की मांग का ही समर्थन किया है। जबकि यह सर्वविदित है कि इस धारा के हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई हैं। विकास के कामों में जबरदस्त तेजी आई है। इस पर अब्दुल्ला पिता-पुत्र एक बार भी नहीं बोले। कारण साफ है, उस वक्त जम्मू-कश्मीर में केंद्र का शासन था। अब जब उनकी पार्टी सत्ता में है तो उन्हें

आतंकी घटनाओं के पीछे साजिश नजर आ रही है।

अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकियों को मारने के बजाए जीवित पकडना़ चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके कि वे किसके लिए काम करते हैं। फारूक अब्दुल्ला से ऐसे बचकाने बयान की उम्मीद कदापि नहीं की जा सकती। फारूक को यह भी बताना चाहिए कि घातक हथियारों से लैस आतंकियों को कौन जीवित पकड़ेगा। जिस तरह का बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है दरअसल वह कहीं न कहीं सुरक्षा बलों और एजेंसियों के मनोबल को प्रभावित करेगा। फारूक ने शक की सुई इन्हीं पर उठाई है। अब जम्मू-कश्मीर के लोग इन आतंकी घटनाओं के लिए फारूक अब्दुल्ला सरकार पर वही सवाल उठा रहें हैं, जो सवाल पूर्व में ये केंद्र सरकार से करते रहे हैं। ऐसे में इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सर्वविदित है कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ये हमले करवा रही है। यह बात फारूक अब्दुल्ला और उनके मुख्यमंत्री पुत्र भी अ%छी तरह से जानते हैं। आईएसआई का आतंकी को पालने-पोसने का लंबा इतिहास रहा है। जम्मू-कश्मीर पर सीमा पार पाकिस्तान में आतंकी कैम्प मौजूद हैं। भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक इसकी गवाह है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकियों को भर्ती करके न सिर्फ ट्रेनिंग देती हैं, बल्कि हथियार और रूपए भी मुहैया कराती हैं।

फारूक अब्दुल्ला भारत की विदेश नीति के मामले में हमेशा से हस्तक्षेप करते रहे हैं। अब्दुल्ला ने कई बार कहा है कि आतंकवाद और जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत को पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए। ऐसे बयानों ने पाकिस्तान को हौसले ही बढ़ाए हैं, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान कई बार भारत से हुई बातचीत के बावजूद सीमा पार से आतंकी भेजने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मौजूदा मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत बंद करके पूरी तरह अलग-थलग कर दिया है। इसकी पहल भी पाकिस्तान ने ही की थी।

इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान लगभग भुखमरी के कगार पर आ पहुंचा है। पाकिस्तान दबे-छिपे तरीके से कई बार भारत से संबंध बहाल करने का प्रयास कर चुका है, किन्तु भारत की तरफ से उसे हर एक ही जवाब मिला है कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते।

फारूक अब्दुल्ला के इस शगुफे के दूसरे निहितार्थ भी हो सकते हैं। अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कई बार कर चुके हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर उमर अब्दुल्ला सरकार को पुलिस प्रशासन की कमान मिल जाएगी। इसके अलावा भी दूसरे अधिकार मिल जाएंगे। सवाल यही है कि जम्मू-कश्मीर में पुलिस और सेना मिलकर भी आतंकवादी पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहे हैं, तब फारूक सरकार कानून-व्यवस्था कैसे संभाल पाएगी। इसके विपरीत संभावना इस बात की ज्यादा है कि पुलिस का अधिकार मिलने के बाद सिफारिश और सरकार के हस्तक्षेप करने से भेदभाव की घटनाएं होंगी। यहां तक की आतंकियों के समर्थकों पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले इस बात की अच्छी तरह ताकीद कर ले कि ऐसा करना कहीं आतंकियों के लिए फायदे का सौदा नहीं साबित हो।

आदिवासियों के भगवान 'धरती आबा' बिरसा मुंडा

विजय मिश्रा 'अमित'

सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर जगमगाता हुआ देश भारत आदिम जाति बाहुल्य देश है। यहां विविध आदिम जातियों की जनसंख्या दस करोड़ से अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या की 8.4 प्रतिशत आबादी आदिम जातियों की है। भारत का हृदय प्रांत छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहां 43 अनुसूचित जनजातियां एवं उनके 162उपसमूह निवासरत हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 30.62 है। जनजातीयों का गौरवशाली इतिहास बताता है कि प्राचीन काल से इस समुदाय ने मां भारती की सुरक्षा में अपना तन- मन- धन सदैव न्योछावर किया है। इस बात के प्रबल साक्षी आदिवासियों के जननायक भगवान बिरसा मुंडा हैं। ब्रिटिश हुकूमत से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, शौर्य,त्याग और बलिदान की गाथा को बिरसा मुंडा के जीवन का एक एक पल व्यक्त करता है। भारत के गौरव ऐसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है।सरकार का यह निर्णय जनजाति सेनानियों के सम्मान, जनजाति संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन तथा जनजाति जीवन शैली को शहरी नागरिकों को जानने का बृहद अवसर प्रदान करेगा। साथ ही छनकर आएगी यह बात असभ्य कहता तुझको सभ्य संसार है, उसे मालूम नहीं आदिमजाति ही सच्चा पालनहार है। आदिम जनजाति समुदाय के सबसे बड़े उद्धारक महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को रांची जिला बंगाल प्रेसीडेंसी के उलिहातु ग्राम में हुआ था, जो कि अब नवगठित राज्य झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है। बिरसा मुंडा ने छोटी उम्र में ब्रिटिश हुकूमत सहित शोषक जमींदारों के खिलाफ बड़े बगावत को अंजाम दिया था। आदिवासियों की गरीबी, अज्ञानता, भोलेपन का लाभ उठाने वाले मिशनरियों के विरुद्ध महाविद्रोह छेड़ दिया था। मिशनरियों द्वारा भोले भाले आदिवासियों को बरगलाते धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जा रहा था। यह सब देखकर विचलित बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के भीतर जन जागरण का सफल अभियान चलाया। जिससे प्रभावित होकर आदिवासी समुदाय उन्हें धरती आबा अर्थात धरती के पिता के नाम से पूजने लगा। आदिवासी पुनरुत्थान के महानायक बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त होना अंग्रेजों को खटकने लगा। मिशनरियों के धर्मांतरण के मार्ग पर बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बन गए थे। तब षडयंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को बंदी बना लिया, यद्यपि उनके विरुद्ध कोई ठोस प्रकरण अंग्रेज नहीं बना पाए। दोष मुक्त होकर उनके कारावास से छूटने और पुन: आंदोलन करने का भय अंग्रेजों के भीतर भरा हुआ था। ऐसी स्थिति में बंदीगृह में बिरसा मुंडा की संदेहास्पद मृत्यु 9 जून 1900 को हो गई।उनकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। करीब पच्चीस वर्ष की अल्पायु में बिरसा मुंडा ने आदिवासी पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किया उससे वह अजर अमर हो गए। महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चलाए क्रांति को उलगुलान नाम दिया गया था। उलगुलान अर्थात महाविद्रोह 1895 से लेकर 1900 तक चला था। उनके संघर्षों का ही सुफल रहा कि 1908 में एक कानून बना,जिसके तहत आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के नाम नहीं किया जा सकता। वह कानून आज भी लागू है। आज भी उड़ीसा, झारखंड, बिहार,मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के आदिवासी अंचलों में बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। अबुआ दिशुम अबुआ राज अर्थात अपना देश अपना राज की अलख जगाने वाले जनजाति अमर शहीद बिरसा मुंडा को सादर नमन।

ट्रम्प की जीत को लेकर इमोशनल होने की जरूरत नहीं

डॉ. प्रकाश हिंदुस्तानी

हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। हमने डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस के पक्ष में अपने-अपने तर्क खोज लिए थे। यहां तक कि पूजा पाठ तक शुरू कर दिया था। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत से हम भारतीयों को बहुत खुश होने की जरूरत है? शायद नहीं! क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, दोनों भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। दोनों ही नेताओं का लक्ष्य अपने देश में मतदाताओं के हितों की रक्षा करना था। अमेरिका में चुनाव परिणामों का असर भारत सहित दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

शेयर बाजार की यह चमक दमक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे से प्रभावित बताई जा रही है। बुधवार, 6 नवंबर को शेयर बाजार का कारोबारी सत्र खत्म होने के बाद सेंसेक्स 901.5। अंक उछलकर 80378 पर बंद हुआ निफ्टी भी 270.75 अंक बढ़ा और 24484 पर बंद हुआ। यह शेयर मार्केट अपना नजरिया है कि उसे भारत-अमेरिका कारोबार में अच्छा भविष्य नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका में रहकर एचवन-बी वीजा पाने का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का क्या होगा? क्या अमेरिका में भारतीय सामान के निर्यात का रास्ता मुश्किल जायेगा? ट्रम्प तो यही कहते आए हैं कि आप्रवासी लोग हमारे लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। ट्रम्प बार-बार यह बात कह चुके थे कि वे पहले अपने देश को ठीक करेंगे। उसकी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे और वह वही करने वाले हैं।

ट्रम्प ने कहा था कि हमारे पास एक ऐसा देश है जिसे हम जैसे लोगों की मदद की दरकार है। हम चाहते हैं कि हमें हमारे देश के लोगों को और बेहतर नौकरियां दे सकें। अवैध रूप से आव्रजन खत्म किया जाना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत का साफ-साफ अर्थ है कि अमेरिकी आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित होगी। उसी तरह से आगे बढ़ाई जाएंगी। अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उद्योगों को अच्छा खासा संरक्षण दिया था और भारत और चीन सहित कई देशों के सामान पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया था। याद है कि

भारत में अमेरिकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के आयात पर ड्यूटी घटाने के लिए उन्होंने साफ-साफ कहा था।चुनाव के प्रचार में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अमेरिका फर्स्ट का नारा आगे भी जारी रखेंगे और वे अमेरिकी माल और सेवाओं पर ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। भारत उसी के दायरे में आ सकता है। ट्रम्प का मानना रहा है कि भारत (अमेरिका के) कारोबारी नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन करता है। ट्रंप चाहते थे कि कोई भी चीज अगर अमेरिका से भारत आयात हो तो उस पर 20% तक ही टैक्स लगाया जाए, उससे अधिक नहीं।

भारत और अमेरिका के बीच करीब 200 अरब डॉलर का वार्षिक कारोबार होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर टैक्स की दरें बढ़ा दी तो उसका नुकसान भारत को हो सकता है। ट्रंप की टैक्स नीतियों के बारे में कहा जाता है कि उससे 2028 तक भारत की जीडीपी में 0.1ब तक की गिरावट हो सकती है। यानी 1% का दसवां हिस्सा हमारी जीडीपी का काम हो सकता है। भारत में अमेरिकी आयात भी महंगा हो सकता है।

ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी हद तक तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और बल मिलेगा। इस बात को कहने के पीछे यही भावना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में क्वाड को मजबूती देते हुए दिखते थे। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 देशों का संगठन है। ट्रम्प के फिर राष्ट्रपति बनने से भारत में हथियारों आयात, भारत और अमेरिका की सेना के संयुक्त अभ्यास आदि में तेजी आ सकती है। इस स्थिति का भारत को फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति रहते हुए चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था।

डोनाल्ड ट्रंप की मानव अधिकार के बारे नीतियां रही हैं भारत के अनुकूल रही हैं। पुलवामा अटैक के दौरान भी उन्होंने साफ कहा था कि भारत को आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका समर्थन करता है जबकि जो बाइडन प्रशासन भारत के मामले में नकारात्मक टिप्पणियां करता रहा है। तीन साल पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह तक कहा था कि हम अपने अपने देशों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक संस्थानों की रक्षा करें। यह बहुत जरूरी है। इसका मतलब यही था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को जो बात कह रही थी, कूटनीति की भाषा में उसे धमकाना कहा जा सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप बड़े और कड़े फैसले लेने के आदी हैं और दुनिया के कई देश उनके कार्य करने के ढंग से नाराज भी थे। ट्रम्प ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, सिक्खों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं हिंदू, ईसाई और दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा और लूट की कड़ी निंदा करता हूं। बांग्लादेश आज अराजकता की स्थिति में है।डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी हिंदुओं को बचाने के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने साफ-साफ कहा कि मैं कुछ लोगों के धर्म विरोधी एजेंडे से हिन्दू अमेरिकी नागरिकों को बचा लूंगा। यानी जैसी अराजकता कनाडा में हुई, वैसी अमेरिका में नहीं होगी।

अमेरिका पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति में कहीं भी जगह नहीं देता। उसकी निगाह भारत पर होती है या फिर अफगानिस्तान पर। ट्रंप फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो भी काम करेंगे, अमेरिकी हितों में ही होगा। संभव है कि कुछ कार्य हमारे फायदे के हो जाएं। ऐसा हुआ तो यह विन विन वाली सिचुएशन होगी।

बंगाल में चुनावी हिंसा और सियासत

सत्येंद्र प्रताप सिंह

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में ही होती है। दरअसल, इस राज्य में दंभ के स्वरों की गिनती में हिंसा का शीर्ष स्थान है और हिंसा को हमेशा शक्ति प्रदर्शन की श्रेणी में रखा गया। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो! चाहे आम चुनाव हो या उप चुनाव ही क्यों न हो! चाहे वह प्री पोल वायलेंस हो या पोस्ट पोल वायलेंस! पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा की गठरी हमेशा बंधी रही।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े भी हालांकि पूरी तरह सटीक नहीं कहे जा सकते। विपक्षी दल व उसके नेता संख्या इससे ज्यादा बताते हैं। मसलन, एनसीआरबी ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं के मामलों में से 12 बंगाल से जुड़े थे।

इसी बरस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एडवाइजरी भेजी। उसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा में 96 लोग मारे गए साथ ही लगातार होने वाली हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। इसके बाद एनसीआरबी की ओर से सफाई आई। ये कहा गया कि उसे पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों से आंकड़ों पर स्पष्टीकरण नहीं मिला है। इसलिए उसके आंकड़ों को फ़ाइनल नहीं माना जाना चाहिए।

एनसीआरबी की उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुईं। जबकि, उस साल अगस्त में सीपीएम ने एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 62 काडरों की हत्या कर दी। हिंसा का जहां तक सवाल है, खासकर 2018 पंचायत चुनाव से 2021 के विधानसभा चुनाव तक राज्य में काफी हिंसा देखने को मिलीं। ख़ासकर विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने तो काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का राज है और विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है।

बंगाल की राजनीति में जब 1980-1990 में बीजेपी

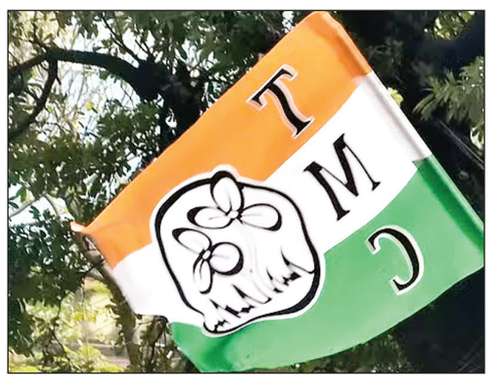

और तृणमूल का अस्तित्व नहीं था तब भी कांग्रेस और वाममोर्चा के बीच हिंसा चरम पर थी। 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने विधानसभा में आंकड़ा पेश किया था जिसमें कहा गया कि 1988-89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई। इनमें 34 सीपीएम के थे और 19 कांग्रेस के। बंगाल की बदहाल स्थिति देख कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। ज्ञापन में दावा था कि 1989 के पहले 50 दिनों में कांग्रेस के 26 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है।

पश्चिम बंगाल में 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े प्रमाण के तौर पर पेश किए जाते हैं। एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई और देश में बंगाल इस मामले में पहले स्थान पर था।

दरअसल, पश्चिम बंगाल देश विभाजन के बाद से ही हिंसा से जूझता रहा। 1979 में सुंदरबन इलाके में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के नरसंहार को आज भी राज्य के इतिहास के सबसे क्रूर अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। साठ के दशक में उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुए नक्सल आंदोलन ने राजनीतिक हिंसा को एक नया आयाम दिया था। किसानों के हो रहे शोषण के विरोध में नक्सलबाड़ी से उठने वाली आवाजों ने उस दौरान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी।

आंकड़े और किस्से बताते हैं कि 1971 में सिद्धार्थ शंकर रे की कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक हत्याओं की रफ्तार तेज हो गई थी। 1977 विधानसभा चुनावों में यही उसके पतन का कारण भी बना। सत्तर के दशक में भी वोटरों को आतंकित कर अपने पाले में करने और सीपीएम की पकड़ मजबूत करने के लिए बंगाल में हिंसा होती रही है।

1998 में ममता बनर्जी की टीएमसी का गठन हुआ और यहां से वर्चस्व की एक और लड़ाई आरंभ हुई जिसने हिंसा को एक नया रूप दे दिया। पंचायत चुनावों के दौरान कई इलाकों में भारी हिंसा शुरू हुई। राज्य के विभिन्न इलाकों में बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व भी पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा की एक प्रमुख वजह है। यह तमाम कारोबार पंचायतों के ज़रिए ही नियंत्रित होते हैं।

पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी पश्चिम बंगाल में राजनीति की बात होती है तो पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है। वहां, हिंसा का नाता चुनाव से नहीं राजनीति से हो गया है। पश्चिम बंगाल में दशकों से राजनीतिक हिंसा का इतिहास है। राजनीतिक हिंसा की शुरुआत नक्सल आंदोलन के साथ हुई।

1960 से 1970 के बीच शुरू हुई नक्सली हिंसा धीरे-धीरे राजनीतिक हिंसा में बदल गई। 1977 में राज्य में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई जो 2011 तक यानी 34 साल तक रही। एक आंकड़े के मुताबिक इन 34 वर्षों के दौरान राज्य में राजनीतिक हिंसा में 30 हजार लोग मारे गए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए नंदीग्राम और सिंगुर आंदोलन को पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस हिंसात्मक तरीके से दबाया वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और 34 साल की सरकार का पतन हो गया।

बहरहाल, 2011 में लेफ्ट सरकार के पतन के बाद लोगों को उम्मीद जगी कि अब सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा-लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल में हिंसा कम नहीं हुई। अब तो बिना किसी चुनाव के भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पर हमला आम बात हो गई है। जबकि 1977 में कांग्रेस और 2011 में लेफ्ट फ्रंट सरकार की विदाई के पीछे कई वजहों में मुख्य वजह राजनीतिक हिंसा भी थी। ऐसे में आखिर कैसे बदलेगी यह तस्वीर!

भारत के पास दुनिया को आत्मिक शांति की राह दिखाने की शक्ति

कृष्णमोहन झा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ कर समाजसेवा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान करने वाले यशस्वी चिकित्सकों में अग्रणी जबलपुर की स्वनामधन्य महिला चिकित्सक डॉ उर्मिला ताई जामदार की पावन स्मृति में योग मणि ट्रस्ट द्वारा संस्कारधानी में आयोजित एक व्याख्यान समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वर्तमान में विश्व कल्याण में हिंदुत्व की प्रासंगिकता जो सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं उन पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से रेखांकित किया है। भागवत ने अपने व्याख्यान में रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास के बीच जारी संघर्ष की चर्चा करते हुए कहा कि दो विश्व युद्धों में बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार के बावजूद आज विश्व में तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा है उसमें सारी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। संघ प्रमुख ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में आगे कहा कि दो विश्व युद्धों ने दुनिया को आस्तिक और नास्तिक, इन दो विचारधाराओं में बांट दिया। आगे चलकर यही संघर्ष का विषय बन गया। इस समय दुनिया में मौजूद परिस्थितियों ने भारत की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया है क्योंकि भारत के पास भौतिक सुख संपदा के साथ आत्मिक शांति देने की शक्ति है। संघ प्रमुख ने पश्चिमी सभ्यता में हुए विकास को अधूरा बताते हुए कहा कि धर्म और राजनीति जैसे क्षेत्रों को व्यापार में बदल दिया गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का सिर्फ व्यावसायिक उपयोग हो रहा है इसलिए समाज में संघर्ष और विभाजन की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को दूर करने के लिए जिस आत्मिक शांति की आवश्यकता है वह सारी दुनिया को भारत के माध्यम से मिल सकती है इसलिए दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हुई हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि आज का विश्व ज्ञान और साधनों से संपन्न है परन्तु उसके पास मानवता के कल्याण का मार्ग नहीं मालूम है। यह मार्ग केवल भारत ही दिखा सकता है परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत ने अपने उस ज्ञान को विस्मृत कर दिया है। सुख सुविधाओं और शांतिपूर्ण जीवन शैली भी उसके बहुत से कारणों में से एक है। हमें उस विस्मृति के गर्त से बाहर निकलना है। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि आधुनिक युग में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है परन्तु उसका गरीबों तक नहीं पहुंचा है जबकि विनाशकारी हथियार हर जगह पहुंच गए हैं। संघ प्रमुख ने सनातन धर्म को मानव धर्म का पर्याय बताते हुए कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है और हिंदुत्व के मूल में भारत की प्राचीन संस्कृति निहित है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण में सहायक हो सकती है । संघ प्रमुख ने कहा कि विविधताओं के साथ एक होकर रहना ही हिंदुत्व है ।हमारे यहां धर्म की अवधारणा सत्य , करुणा, शुचिता और तपस है । यही धर्म दर्शन दुनिया के साथ साझा करने की जिम्मेदारी भारत के ऊपर है। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने परंतु कुछ लोग इसकी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा यदि वे भारत के विश्व का मार्गदर्शक बनने की बात करें तो कोई विवाद नहीं होता लेकिन जब वे यह कहते हैं कि हिंदुत्व में विश्व का मार्गदर्शक बनने की क्षमता है तो विवाद खड़ा हो जाता है।

कोणार्क सूर्य मंदिर के शिखर पर लगे पत्थर के बारे में जो बताया जाता है वह कितना सच है

ओडिशा के कोणार्क शहर में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल हैं। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण हजारों वर्षों पूर्व हुआ माना जाता है लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ई. के बीच हुआ था। भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों में शुमार कोणार्क सूर्य मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। स्थानीय लोग यहां सूर्य-भगवान को बिरंचि-नारायण भी कहते थे।

कोणार्क सूर्य मंदिर की खासियत

केसरी वंश के राजा द्वारा निर्मित इस मंदिर की शिल्पकला दर्शनीय है। मंदिर का निर्माण सूर्य के काल्पनिक रथ का रूप देकर किया गया है। सूर्य मंदिर चौकोर परकोटे से घिरा है। इसके तीन तरफ ऊंचे-ऊंचे प्रवेशद्वार हैं। पूरब दिशा में मुख्य द्वार है जिसके सामने समुद्र से सूर्य उदय होता दिखाई पड़ता है। इसमें सूर्य भगवान को अपने विशाल चौबीस पहियों तथा सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर दिनभर की यात्रा के लिए निकलते हुए दिखाया गया है। रथ के सात घोड़ों को सूर्य के प्रकाश के सात रंगों तथा चौबीस पहियों की परिक्रमा के प्रतीक रूप में दिखाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के स्वर्णकाल तथा कलिंग शैली की शिल्पकला का प्रतीक है। इस मंदिर की दीवारों पर पत्थर की नक्काशी की हुई अनेक आकर्षक प्रतिमाएं हैं। सूर्य भगवान के रथ की अलंकृत नक्काशी वाला यह बेजोड़ मंदिर भव्यता में अद्भुत है।

कोणार्क मंदिर से जुड़ी अजब कथा

कई कथाओं में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुम्बकीय पत्थर लगा है जिसके प्रभाव से, कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागरपोत इस ओर खिंचे चले आते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। एक अन्य कथा में उल्लेख मिलता है कि शिखर पर लगे इस पत्थर के कारण पोतों के चुम्बकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बता पाते थे इसलिए कुछ आक्रांता इस पत्थर को निकाल कर ले गये जिससे मंदिर को नुकसान हुआ था। हालांकि यह सब कही-सुनी बातें हैं इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

कोणार्क मंदिर देखने कैसे आएं

यदि आप भी कोणार्क सूर्य मंदिर आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर और पुरी से यहां आसानी से आ सकते हैं। ओडिशा पर्यटन विकास निगम की ओर से यहां भ्रमण की भी व्यवस्था कराई जाती है। वैसे कोणार्क में रहने की भी पर्याप्त व्यवस्था है। पर्यटक चाहें तो भुवनेश्वर से यहां आकर भ्रमण कर के उसी दिन वापस लौट सकते हैं। कोणार्क में रहने के लिए पर्यटन विभाग के लाज, टूरिस्ट बंगला और निरीक्षण भवन भी हैं।

कोणार्क का समुद्र तट भी अवश्य देखें

कोणार्क का समुद्र तट विश्व के सुंदरतम तटों में से एक माना गया है। यहां समुद्र के रेतीले गुट का आनंद उठाया जा सकता है। समुद्र की खूबसूरती निहारते हुए उठती-गिरती लहरों को देखना मंत्रमुग्ध कर देता है। यह एक सुंदर पिकनिक स्थल भी है। समुद्र तट सूर्य मंदिर से तीन किलोमीटर दूर है। इसके अलावा कोणार्क की दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह देखने के लिए मंदिर के पास ही स्थित संग्रहालय भी जा सकते हैं।

गुजरात का यह मंदिर दिन में दो बार हो जाता है गायब, जानिए क्या है रहस्य

भारत में कई हिस्सों में भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं जहाँ दूर-दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिन में दो बार गायब हो जाता है। जी हाँ, गुजरात में स्थित स्तंभेश्वर मंदिर को 'गायब मंदिर' भी कहा जाता है। देश-विदेश से शिव भक्त अपनी मनोकमना पूर्ण होने की कामना के साथ इस मंदिर में आते हैं। आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत मंदिर के बारे में -

वडोदरा के पास स्थित है स्तंभेश्वर मंदिर

स्तंभेश्वर मंदिर गुजरात के जम्बूसार तहसील में कवि कंबोई गांव में स्थित है। यह मंदिर वडोदरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित होने के कारण वडोदरा के पास सबसे लोकप्रिय दार्शनिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना है और इसे %गायब मंदिर% भी कहा जाता है। सालभर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। खासतौर पर सावन के महीने में इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर-दूर से महादेव के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं।

स्कंद पुराण में मिलता है उल्लेख

स्कन्द पुराण में दिए गए उल्लेख के अनुसार स्तम्भेश्वर मंदिर को भगवान कार्तिकेय के ताड़कासुर नाम के राक्षस को नष्ट करने के बाद स्थापित किया था।

कहा जाता है कि राक्षस ताड़कासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कीऔर भोलेनाथ ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान मांगने को कहा। तब ताड़कासुर ने आशीर्वाद माँगा कि भगवान शिव के छह दिन के पुत्र के अलावा कोई भी उसे मार न सके। उसकी इच्छा पूरी होने के बाद, ताड़कासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तब ताड़कासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भगवान कार्तिकेय की रचना की। ताड़कासुर को मारने वाले भगवान कार्तिकेय भी उसकी शिव भक्ति से प्रसन्न थे। इसलिए, प्रशंसा के संकेत के रूप में, उन्होंने उस स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया जहां ताड़कासुर का वध किया गया था।

एक अन्य संस्करण के अनुसार, ताड़कासुर को मारने के बाद भगवान कार्तिकेय खुद को दोषी महसूस कर रहे थे क्योंकि ताड़कासुर राक्षस होने के बाद भी भगवान शिव का भक्त था। तब भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को यह कहते हुए सांत्वना दी कि आम लोगों को परेशान करके रहने वाले राक्षस को मारना गलत नहीं है। हालाँकि, भगवान कार्तिकेय शिव के एक महान भक्त को मारने के अपने पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए, भगवान विष्णु ने उन्हें शिव लिंग स्थापित करने और क्षमा के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी।

मंदिर के गायब होने के पीछे है यह वजह

स्तंभेश्वर मंदिर के गायब होने के पीछे की वजह प्राकृतिक है। दरअसल, यह मंदिर समुद्र के किनारे से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर जलमग्न हो जाता है। फिर कुछ जो देर में जल का स्तर घट जाता है जिससे मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है से प्रकट होता है। चूंकि समुद्र का स्तर दिन में दो बार बढ़ जाता है इसलिए मंदिर हमेशा सुबह और शाम के समय कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। इस नज़ारे को देखने के लिए श्रद्धालु दूर-दूर से इस मंदिर में आते हैं।

बिना तेल और घी के जलता है दीया, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े चमत्कारी रहस्यों के बारे में कितना जानते हैं आप?

भारत में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। यह मंदिर है भगवान तिरुपति बालाजी का जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मन्दिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वैंकटेश ?वर बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित है और तिरुपति के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ दर्शन कर ले उसके भाग खुल जाते हैं। इस मंदिर की लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ है पर क्या आप मंदिर के चमत्कारी रहस्यों के बारे में जानते हैं। आज हम आपको इन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं-

मान्यता है कि जब भगवान की पूजा की जाती है तो उनकी मूर्ति मुस्कुराने लगती है। भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति में माता लक्ष्मी भी समाहित है। मान्यता है कि भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर की मूर्ति इस मंदिर में स्वयं प्रकट हुई थी।

कहा जाता है भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति पर लगे हैं बाल असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं।

जब आप मंदिर के गर्भ गृह के अंदर जायेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकेटेश्वर की मूर्ति गर्भ गृह के मध्य में स्थित है, पर जब आप गर्भ गृह से बाहर आकर मूर्ति को देखेंगे तो प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है।

तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित है लेकिन फिर भी भगवान की मूर्ति से समुद्र की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान की यह मूर्ति समुद्र से प्रकट हुई थी इसलिए इससे समुद्र की आवाज सुनाई देती है।

तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर के द्वार पर एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु धरती पर माता लक्ष्मी को ढूंढने आये थे तो यह छड़ी उन्हें उनका पता बता रही थी।

ऐसी मान्यता है कि यह वहीं छड़ी है जिससे बचपन में भगवान वेंकटेश्वर जी को चोट लगी थी। चोट का निशान आज भी उनकी मूर्ति के चेहरे पर है। इसलिए हर शुक्रवार उनके चेहरे पर चन्दन का लेप लगाया जाता है।

श्री तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में श्रृंगार, प्रसाद के चढ़ाये जाने वाली सामग्री तिरुपति बालाजी के गांव से आती है। यह गांव मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है।

श्री वेंकेटेश्वर बालाजी मंदिर में एक ऐसा दीया रखा हुआ है जो हमेशा जलता रहता है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था यह बात अब तक रहस्य बनी हुई है।

सर्दियों में लेना है स्नोफॉल का मजा तो जरूर जाएं भारत की इन 5 खूबसूरत जगहों पर

भारत में कई ऐसी जगहे हैं जो अपनी खूबसूरत वादियों और सर्दियों में बर्फबारी के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। अगर आप अपना विंटर वेकेशन प्लान कर रहे हैं और इस बार परिवार के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं आप स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं-

शिमला : स्नोफॉल का जिक्र होते ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का नाम सबसे पहले जहन में आता है। यह स्नोफॉल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां के हरे भरे पहाड़, ऊंची चोटियां ठंड के दिनों में बर्फ से पूरी तरह ढंककर और भी खूबसूरत दिखते हैं। शिमला को लॉन्ग मून नाइट्स यानी लंबी चांदनी रातों का मौसम भी कहा जाता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहां बर्फबारी का आनंद लिया जा सकता है। इस मौसम में आप यहां स्कींग का भी मज़ा ले सकते हैं। शिमला में आइस स्केटिंग दिसंबर से फरवरी तक होती है।

गुलमर्ग : धरती के स्वर्ग जम्मू-कश्मीर में स्थित गुलमर्ग बेहद खूबसूरत जगह है और यहां बर्फबारी का आनंद लेने का अनुभव बहुत खास होता है। सर्दियों के मौसम में गुलमर्ग में चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखती है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। सर्दियों के मौसम में गुलमर्ग में स्कीइंग करने वालों की भी भीड़ जुटती है। यहां की कुदरती खूबसूरती आपका मन मोह लेगी।

औली : उत्तराखंड का सबसे पुराना शहर औली बेहद सुंदर है। बर्फबारी के समय यह किसी स्वपनलोक सा दिखता है। औली भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ स्कीइंग के लिए मशहूर है। यहां देवदार पेड़ों की लंबी कतार है। बर्फ से ढके जंगलों के बीच सैर करके आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

कुफरी : शिमला के अलावा हिमाचल प्रदेश में स्थित कुफरी भी स्नोफॉल के दौरान बहुत सुंदर दिखता है और लोग यहां स्कींग के लिए आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहां सैलानियों की काफी भीड़ जुटती है। यहां लोग पहाड़ों के बीच रोमांच का मज़ा लेते हैं। हाइकिंग, स्कीइंग, खूबसूरत नजारे, देवदार के लंबे-लंबे पेड़ और सुहानी सर्द हवा का मज़ा लेना है तो कुफरी ज़रूर जाएं।

कुल्लू-मनाली : पॉप्युलर हनीमून डेस्टिनेशन कुल्लू मनाली में भी बर्फबारी का मज़ा लिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का यह हिल स्टेशन भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। रोमांच के शौकीनों की तो यह पहली पसंद है। दिसंबर जनवरी में आकर यहां आप भी स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने पं. नेहरू को दी श्रद्धांजलि

नईदिल्ली। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती के मौके पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, उनकी जयंती के अवसर पर, मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देता हूं। जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है जिसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बीच, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उन्हें 135 जयंती पर शत-शत नमन किया। राजनीतिक जगत के कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया के जरिए पंडित नेहरू को याद किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आधुनिक भारत के निर्माता, स्वतंत्रता संग्राम के निर्माता को सादर नमन उन्होंने एक पोस्ट में कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, निडर, दूरदर्शी, समावेशी- भारत के यहूदी के ये मूल्य हमारे आदर्श और हिंदुस्तान के स्तंभ हैं और हमेशा रहेंगे।

सुनील जाखड़ ने हरियाणा विस जमीन आवंटन का किया विरोध

चंडीगढ़। पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हरियाणा को अपना विधानसभा परिसर बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित करने के केंद्र के कदम का विरोध किया और इसे रद्द करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में जाखड़ ने कहा कि जमीन आवंटित करने का केंद्र का कदम पंजाबियों को भावनात्मक रूप से आहत करेगा क्योंकि पंजाब की राजधानी होने के नाते चंडीगढ़ महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। यह राज्य के लोगों के लिए गहरी भावना का विषय है। जाखड़ ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राज्य को मिले घावों को भरने के लिए कई प्रयास किए हैं। हरियाणा के लिए भूमि आवंटित करने का कदम पंजाब की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ऊपर उठाने के पीएम के प्रयासों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और इस निर्णय को रद्द करने की अपील करता हूं।

आप विधायक अमानतुल्लाह खान कोर्ट ने दी जमानत

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपये के जमानत बांड और एक मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में एजेंसी द्वारा उनकी हिरासत को अवैध करार दिया। खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, लेकिन आरोपपत्र में अपेक्षित मंजूरी नहीं है। यह तब हुआ जब अदालत ने खान के मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, इस पर अपना आदेश सुनाया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मामले में आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देगा डोमिनिका

रोसेउ। डोमिनिका की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। डोमिनिका की सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना में आयोजित होने जा रहे आगामी भारत-कैरीकोम सम्मेलन के दौरान इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। डोमिनिका सरकार के बयान में बताया गया है कि डोमिनिका की राष्ट्रपति सिलवेनी बर्टन प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित करेंगी। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एक बहुमूल्य उपहार देते हुए कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 70 हजार डोज की आपूर्ति की थी। प्रधानमंत्री मोदी की इसी उदारता को पहचानते हुए डोमिनिका की सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने डोमिनिका को स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी के क्षेत्र में भी काफी मदद की है। भारत द्वारा डोमिनिका में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में भी मदद की जा रही है।

विधानसभा चुनाव में नहीं होने देंगे वोट जिहाद : नितेश राणे

मुंबई। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक नितेश राणे ने कहा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद न होने पाए। नफरती भाषण के मामलों में अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर नितेश राणे ने कहा कि उन्हें इसका कोई डर नहीं है। एक इंटरव्यू में भाजपा विधायक ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और सिर्फ अपने धर्म और समुदाय का पक्ष लिया है। राणे ने कहा कि एक तरफ जिहादी मानसिकता वाले लोग, रोहिंग्या और बांग्लादेशी संविधान का पालन करने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे शरिया कानून के हिसाब से सारे काम करते हैं। अगर आप हिंदू-मुस्लिम के बीच शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए कानून समान होना चाहिए तो फिर आप लव जिहाद, वोट जिहाद और लैंड जिहाद क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको अपने समुदाय को यह बोलने की जरूरत है कि वे मोदी सरकार के खिलाफ वोट करें?

पहले चरण में हो चुका जेएमएम-कांग्रेस का सफाया

एक-एक घुसपैठिए को चुन कर झारखंड के बाहर भेजेगी भाजपा: अमित शाह

रांची। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को झारखंड के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, झारखंड तो समृद्ध है, झारखंडी गरीब हैं। क्योंकि जेएमएम सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वादा करते हुए कहा कि आप 20 तारीख को कमल के निशान का बटन दबाइए, हम झारखंड में ऐसे कारखाने लगाएंगे, जिससे यहां का युवा दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए नहीं जाएगा।

शाह ने आरोप लगाया कि जेएमएम सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर है। ये घुसपैठिए, झारखंड में आते हैं और हमारी बच्चियों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, यहां कमल की सरकार बना दो, हम आपसे वादा करते हैं, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। उन्होंने कहा कि जेएमएम सरकार के साथ झारखंड में घुसपैठियों का भी समय समाप्त होगा। एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुन प्रदेश से बाहर भेजने का काम भाजपा करेगी।

भाजपा नेता ने दावा किया कि हम ऐसा कानून लेकर आयेंगे, जिसमें आदिवासी बच्ची के साथ शादी करने से भेंट के माध्यम से आदिवासियों की जमीन आप (घुसपैठिए) हड़प नहीं सकते और जिन्होंने हड़पा है, वो वापस भी करायेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड ने वर्षों तक नक्सलवाद को झेला है। नक्सलवादियों ने झारखंड को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी जी ने झारखंड को 10 साल में नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में जो बचा कुचा नक्सलवाद है, 2026 से पहले हम उसे भी समाप्त करेंगे। हम 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे।

अमित शाह ने कहा कि सोनिया जी को अपने बेटे को लांच करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लांच किया, लेकिन लैंड ही नहीं होता है। ये प्लेन, 20 बार क्रैश हो चुका हैं और 21वीं बार भी देवघर एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश होने वाला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कांग्रेस को सलाह दी कि वादे उतने ही करो जो पूरे हो सकें। कनार्टक, हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वो करते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर होती है।

शाह ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस (जम्मू-कश्मीर में) धारा 370 वापस लाना चाहती है। कश्मीर भारत का है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब पाकिस्तान से आतंकवादी हमले अक्सर होते थे। जब पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक से आतंकवाद का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड ने नक्सलवाद झेला है। उन्होंने झारखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीएम मोदी ने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में झामुमो-कांग्रेस का सफाया हो गया है।

बंटवारे पर भरोसा करती है कांग्रेस : मोदी

- **संभाजीनगर में बोले प्रधानमंत्री- अघाड़ीवालों को विकास से मतलब नहीं**

मुंबई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को छत्रपति संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और अन्य महायुति नेता भी मौजूद रहे। अपने संबोधन की शुरूआत में पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल नई सरकार चुनने का ही चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक ओर संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी ओर औरंगजेब के गुणगान करने वाले लोग हैं।

मोदी ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर को ये नाम देने की मांग बालासाहेब ठाकरे ने उठाई थी। अघाड़ी सरकार की 2.5 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। जबकि महायुति सरकार ने आते ही इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया। हमने आपकी इच्छा को पूरा किया, हमने बालासाहेब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई थी? इसी कांग्रेस पार्टी को, अघाड़ी वालों को... जिसके पाले-पोसे हुए लोग इस फैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक चले गए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। बीजेपी और महायुति इसी संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। आज समृद्धि महामार्ग संभाजी नगर से होकर गुजर रहा है। मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई से सीधे जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ ही, हमारी सरकार, विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विठ्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी महामार्ग का निर्माण करवाया है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लोग दशकों से मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। मराठा गौरव से जुड़ा ये काम भी भाजपा ने ही पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। उन्होंने कहा कि ये अघाड़ी वाले आपको बूंद-बूंद पानी के लिए तरसाएंगे। आपसे अनुरोध है कि इन अघाड़ी वालों को घुसने ही मत देना।

मोदी ने कहा कि महायुति के लिए हमारा किसान, अन्नदाता है, विकसित महाराष्ट्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। यहां कपास के किसान बहुत बड़ी मात्रा में हैं। हमारी सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए भी हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है ताकि सत्ता पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, वो उन विज्ञापनों में साफ दिख रहा है। कांग्रेस, आरक्षण को देश के खिलाफ और मेरिट के खिलाफ बताती थी।

महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला

मुंबई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि संविधान की लाल किताब कोरी है क्योंकि उन्होंने इसे कभी नहीं पढ़ा है। गांधी ने कहा कि संविधान में भारत की आत्मा और बिरसा मुंडा, डॉ बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों द्वारा परिकल्पित सिद्धांत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं जनसभाओं में जो संविधान दिखाता हूं, वो खाली है। नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान खाली है, क्योंकि उन्होंने कभी इसे पढ़ा ही नहीं है। वे कहते हैं कि राहुल गांधी लाल रंग का संविधान दिखाता है। मोदी जी, इसके रंग से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है, हम उसकी रक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान में गांधी द्वारा प्रदर्शित लाल किताब को शहरी नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश की। वहीं, गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और भाजपा ऐसी टिप्पणियां करके राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। लेकिन बीजेपी-आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी में बहुत बड़ा फर्क है। आपके इसी अधिकार को बचाने के लिए बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े थे। आज यही सोच लेकर नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग घूम रहे हैं। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घोषणापत्र पर प्रकाश डालते हुए, गांधी ने कहा कि महिलाओं, किसानों और युवाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता और मुफ्त बस यात्रा, 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी और 4,000 रुपये प्रति माह सहायता जैसे प्रावधानों से संरक्षित किया जाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

विराट और रोहित के लिए आखिरी मौका?

नईदिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। पर्थ की तेज पिच पर यह टेस्ट मैच चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर बल्लेबाजों के लिए यहां रन बनाना आसान नहीं होगा। क्योंकि पर्थ की पिच आम तौर पर तेज और उछाल वाली होती है, जो गेंदबाजों को फायदा देती है।

ऋषभ पंत, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ जैसे स्टार बल्लेबाजों के लिए यह मैच अहम होगा। पंत का फॉर्म और उनकी आक्रामक बैटिंग के साथ-साथ कोहली और स्मिथ के बीच की जंग भी दर्शकों को आकर्षित करन के लिए तैयार है। इसके साथ ही यह मैच दोनों टीमों के लिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपने लिए अंक जुटाने का भी मौका होगा।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने भारतीय क्रिकेट आइकन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में एक खास बयान दिया है। क्लार्क का सुझाव है कि आगामी सीरीज दोनों खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर वे अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं तो उनका करियर मुश्किल में पड़ सकता है। 22 नवंबर को पर्थ में होने वाले सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा बाहर रह सकते हैं।

ईएसपीएन के पॉडकास्ट पर चर्चा में क्लार्क ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यह उनका आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें संन्यास लेना होगा। उन्हें टीम से नहीं निकाला जाएगा। टीम का कप्तान होने से आप पर बहुत दबाव पड़ता है। अगर आप एक दशक से ज़्यादा समय से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ रहे हैं, तो आप पर दबाव और भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि विराट पर सबसे ज़्यादा दबाव होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 110 अंक टूटा निफ्टी 24 हजार से नीचे

नईदिल्ली। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और बढ़ती महंगाई के बीच इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाल, बीएसई सेंसेक्स 110.64 अंक या 0.14 प्रतिशत की गिरावट लेकर 77,580.31 पर बंद हुआ। इससे पहले, यह इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 254.5 अंक चढ़कर 77,945.45 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में आज 77,424.81 और 78,055.52 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ह्स्श्व) का निफ्टी 50 26.35 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट लेकर 23,532.70 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की ही तरह, निफ्टी 50 भी शुरुआती कारोबार में 86.25 अंक की बढ़त के साथ 23,645.30 अंक पर पहुंच गया था। निफ्टी में आज 23,484.15 और 23,675.90 के रेंज में कारोबार हुआ।

थोक महंगाई दर अक्तूबर में बढ़कर 2.36% हुई

नई दिल्ली। भारत की थोक महंगाई दर अक्तूबर में सालाना आधार पर बढ़कर 2.36 प्रतिशत हो गई। सितंबर में यह 1.84 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण यह इजाफा हुआ। गुरुवार को इससे जुड़े सरकारी आंकड़े जारी किए किए। रॉयटर्स की ओर से किए गए सर्वेक्षण में, थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करके मापी गई थोक मुद्रास्फीति या थोक महंगाई दर 2.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई थी। इससे पहले, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्तूबर में अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 14 महीने के उच्च स्तर 6.2% पर पहुंच गई, जो सितंबर में 5.5% थी। महंगाई बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखने लगने हैं। इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से मौद्रिक नीति में ढील का फैसला लेने में देरी हो सकती है।

एसएंडपी ने 6.5-7% सालाना ग्रोथ का लगाया अनुमान

नईदिल्ली। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्च 2027 तक तीन वित्त वर्षों में सालाना 6.5-7 प्रतिशत के बीच बढ़ने का गुरुवार को अनुमान लगाया। बुनियादी ढांचे पर खर्च और निजी खपत से वृद्धि को गति मिलना इसकी मुख्य वजह रहेगी। अपनी वैश्विक बैंक परिदृश्य रिपोर्ट में एसएंडपी ने कहा कि अच्छी आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता को समर्थन देना जारी रखेंगी, जबकि स्वस्थ कॉर्पोरेट बही-खाते, सख्त 'अंडरराइटिंग' मानक और बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाएं परिसंपत्ति गुणवत्ता को और स्थिर करेंगी। एसएंडपी ने कहा, '' भारत का बुनियादी ढांचा व्यय और निजी खपत मजबूत आर्थिक वृद्धि को समर्थन देगा। हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-2027 (31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना 6.5-7.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

भारत सौर उत्पादों का आयातक से बना निर्यातक

नई दिल्ली। भारत का सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2022 के मुकाबले 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 2 अरब डॉलर हो गया है। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) और जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स के मुताबिक, इस बदलाव से भारत सौर उत्पादों का कुल आयातक से निर्यातक बन गया है। भारत द्वारा किए जाने वाले सौर उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी की वजह 'चीन प्लस वन' की रणनीति होना है। इस कारण भारत अन्य देशों के लिए सौर उत्पाद आयात का एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका घरेलू सौर पीवी उत्पाद निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है।

निजी खपत से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

डॉ. जयंती लाल भण्डारी

हाल ही में एक नवंबर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'एशिया प्रशांत के लिए क्षेत्रीय आर्थिक अनुमान 2024' में कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है तथा निवेश और निजी खपत इसकी वृद्धि को गति दे रहे हैं। रिपोर्ट में भारत की विकास दर को पहले के 6 ।8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। गौरतलब है कि दिवाली के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती संबंधी शुभ संकेत उभरकर सामने आ रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक है। देश कृषि, उद्योग-कारोबार, बैंकिंग क्षेत्र और गैरबैंकिंग वित्तीय क्षेत्र प्रणाली के स्तर पर काफी मजबूत बना हुआ है। विकास और मुद्रास्फीति का संतुलन बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि भू-राजनीतिक संकट, भू-आर्थिक बिखराव और किसी तरह की चरम मौसमी घटनाएं, जो बाहरी मांग को प्रभावित कर सकती हैं और ये भारत की वृद्धि के लिए एक तरह का बड़ा जोखिम होंगी, लेकिन भारत अपने मजबूत आर्थिक घटकों से उनका मुकाबला करने में सक्षम होगा।

उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई में नरमी आएगी और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7 ।2 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस समय ग्लोबल फंड का भारतीय बांड में किया जा रहा निवेश उभरते बाजारों में ऊंचाई पर रेखांकित हो रहा है। पिछले वर्ष 2023 में भारतीय बांड में जो विदेश निवेश 70,627 करोड़ रुपए का था, वह इस वर्ष 2024 में करीब 88 प्रतिशत बढ़कर अक्तूबर तक 1.33 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। निश्चित रूप से भारत की विकास दर उभरते हुए देशों की तुलना में ऊंचाई पर होगी।

स्थानीय और घरेलू बाजार की मजबूती अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगी। वैश्विक खाद्यान्न संकट के बीच भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा में मददगार देश की भूमिका बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तथा कई देशों के अनुरोध पर भारत ने गैरबासमती चावल यानी सफेद चावल के निर्यात पर जुलाई 2023 से लगाई गई रोक को हटा लिया है।

भारत के इस निर्णय से दुनिया के कोने-कोने में चावल आयातक देशों के करोड़ों चावल उपभोक्ताओं को राहत मिली है। जहां भारत दुनिया के 150 से अधिक देशों के लोगों की खाद्य जरूरतों के लिए खाद्य निर्यात करता है, वहीं दुनिया के 185 से अधिक देशों के करोड़ों लोगों के लिए सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की आपूर्ति करने वाला विश्वसनीय देश भी है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बढ़ने पर शेयर बाजार में तेज गिरावट और महंगाई की चुनौतियों के बीच भी भारत अपने मजबूत आर्थिक घटकों और ऊंचाई पर स्थित 700 अरब डॉलर से अधिक के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से किसी भी आर्थिक जोखिम का सरलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होगा।

हम उम्मीद करें कि आगामी दिनों में भारतीय शेयर बाजार की राह कठिन नहीं होगी, कॉर्पोरेट आय को बढ़ावा मिलेगा और शेयर बाजार को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाने में घरेलू फंडों की अहम भूमिका होगी। हम उम्मीद करें कि सरकार के द्वारा कृषि सुधारों, मेक इन इंडिया, निर्यात बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी बढ़ाने के रणनीतिक प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा देश का आम आदमी भी विकास की डगर पर आगे बढ़ेगा।

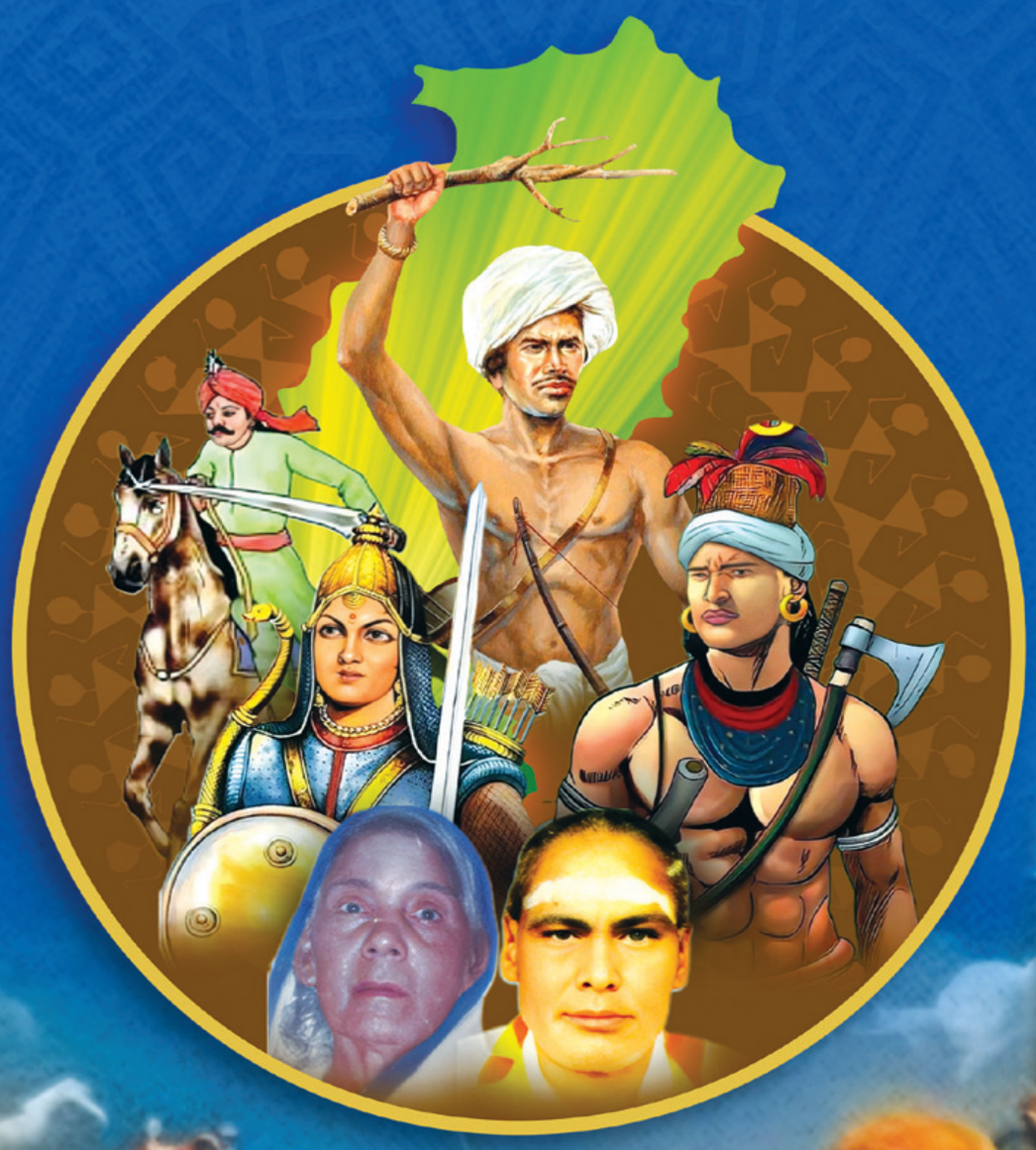

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.